● वर्ष-3
● अंक-42
रायपुर, बुधवार
27 सितंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› प्रकृति की शक्ति कहलाते हैं...

22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री होंगे शामिल

दिसंबर तक पूरा होगा राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर

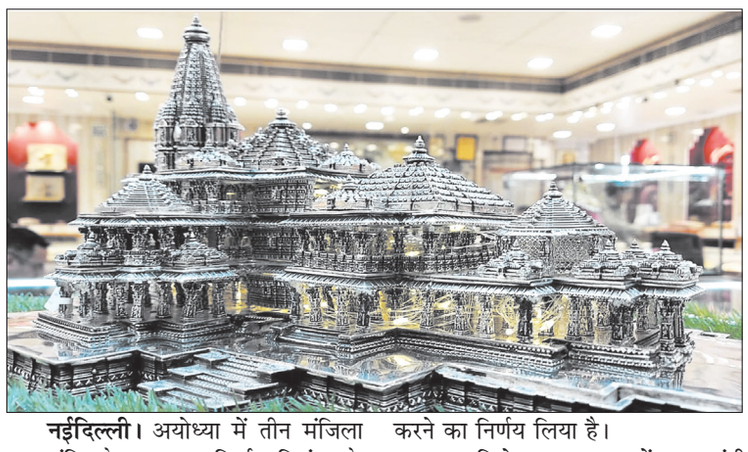

नईदिल्ली। अयोध्या में तीन मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा समारोह अगले साल 22 जनवरी को होगी। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि 15 से 24 जनवरी तक अनुष्ठान होगा और इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने का समय तय हो गया है। वे 22 जनवरी को आएंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इसके लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद राम लला के अभिषेक की प्रक्रिया शुरू करने और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा (प्रतिष्ठा) का 10 दिवसीय अनुष्ठान करने का निर्णय लिया है।

एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर में हर वर्ष रामनवमी के दिन दोपहर बारह बजे सूर्य की किरणें श्रीराम की मूर्ति पर पड़ें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गर्भ गृह में दो मूर्तियां होंगी एक चल और एक अचल। एक श्रीराम की बाल्यावस्था की और दूसरी रामलला की। उन्होंने कहा कि भगवान चार या पांच वर्ष की आयु के होंगे और मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। उन्होंने कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन लगभग सवा लाख दर्शनार्थियों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है।

अब कुछ देश एजेंडा नहीं चला सकते- जयशंकर

संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा- सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद पर एक्शन सही नहीं

नईदिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और कनाडा को आइना दिखाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने भाषण में जी20 की कामयाबी की बात तो की ही। लेकिन जयशंकर ने खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बने कनाडा का भी मुद्दा छेड़ा। यूएन सहित कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत आतंकवाद को पनाह देने वाले देशो के खिलाफ भारत मुखर रहा है। ऐसे देशों में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। लेकिन अब इस लिस्ट में कनाडा भी जुड़ गया है। एस जयशंकर ने हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कनाडा विवाद के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि सियासी सबूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि भारत की ओर से नमस्ते। विश्वास के पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जगाने के इस यूएनजीए के विषय को हमारा पूरा समर्थन है। यह हमारी आकांक्षाओं और

लक्ष्यों को साझा करते हुए हमारी उपलब्धियों और चुनौतियों का जायजा लेने का एक अवसर है। वास्तव में दोनों के संबंध में भारत के पास साझा करने के लिए बहुत कुछ है। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया अभूतपूर्व तनाव के दौर से गुजर रही है। इसके साथ ही कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारी को भलि-भांति समझता है। भारत ने जी20 की अध्यक्षता की। कूटनीति और बातचीत ही तनाव को कम कर सकता है। विकासशील देश तनाव से गुजर रहे हैं। ईस्ट वेस्ट नार्थ साउथ में गैर बराबरी है।

एस जयशंकर ने कहा कि अब अन्य देशों की बात भी सुननी पड़ेगी और केवल कुछ देशों का एजेंडा नहीं चल सकता है। दिल्ली में जी20 समिट में कई रिफॉर्म किए गए। इससे हमें 125 देशों से सीधे सुनने और उनकी चिंताओं को जी20 एजेंडा पर रखने में सक्षम बनाया गया। परिणामस्वरूप, जो मुद्दे सामने आए वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लायक को निष्पक्ष सुनवाई मिली। इससे भी अधिक, विचार-विमर्श ने ऐसे परिणाम दिए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत महत्व रखते हैं। एस जयशंकर ने कहा कि जी20 में ग्लोबल साउथ की आवाज हमने उठाई। भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ जी20 का सदस्य बना। जी20 के घोषणापत्र में सभी देशों की बात सुनी गई। इंडो पैसेफिक में क्वाड का अहम रोल है। विश्व मित्र की तरफ हम सभी बढ़े हैं।

अपने विचार-विमर्श में हम अक्सर नियम-आधारित आदेश को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं। इसमें समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान भी शामिल है। लेकिन सारी बातचीत के लिए, अभी भी कुछ राष्ट्र ही एजेंडा को आकार देते हैं और मानदंडों को परिभाषित करना चाहते हैं। यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता और न ही इसे चुनौती दिए बिना जारी रखा जा सकता है। एक बार जब हम सब इस पर ध्यान देंगे तो एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और लोकतांत्रिक व्यवस्था निश्चित रूप से सामने आएगी।

बेइज्जती का शौकीन पाकिस्तान

संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कश्मीर की दुहाई देने वाला पाकिस्तान न्यूयार्क से आई तस्वीरों को देख शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के राजनीतिक दल यूनाइटेड पीपुल्स कश्मीर पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। पाकिस्तान के लोग कई महीनों से महंगाई और आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर हैं। लेकिन अब

तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में उन्हें मजबूर होकर यहां आना पड़ा। पीटीएम यूरोप के समन्वयक मलिक बाज़ई ने कहा कि सिर्फ पश्तून, बलूच, सिंधी, कश्मीरी ही नहीं, कोई भी समुदाय पाकिस्तान में खुश नहीं है... पाकिस्तानी सरकार ने इन सभी समुदायों को गुलाम बना लिया है... पाकिस्तान सरकार की नज़र प्राकृतिक पर है पश्तूनों की संपत्ति... वे वहां आते हैं, पश्तूनों को आतंकित करते हैं, लोगों को लूटते हैं, उन्हें लूटते हैं, इलाके पर बमबारी करते हैं... इन सबके पीछे पाकिस्तानी सरकार है... वे हमारे शहरों पर बमबारी करने के लिए युद्ध के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। फ़ज़ल-उर-रहमान अफ़रीदी ने कहा कि पश्तून अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुज़र रहे हैं। पाकिस्तानी सेना घोर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो कि इसका व्यवस्थित उपयोग है। पाकिस्तानी सेना द्वारा अत्याचार।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने रायपुर स्थित निवास में विराजे भगवान श्री गणेश के पंडाल में पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान श्री गणेश की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ काम कर रही: भाजपा

नईदिल्ली। दिल्ली में भाजपा नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की सरकार पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भाजपा नेता ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश की सरकार रोक रही है। भाजपा नेता और प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं को रोककर सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है।

भाजपा ने आरोप लगया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में लोगों से कई झूठे वादे किए हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आप सबको ज्ञात है कि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है। कल राहुल गांधी

छत्तीसगढ़ में थे, वहां उन्होंने कई झूठे वादे लोगों से किए। आज वक्त आ चुका है कि भाजपा और देश एवं छत्तीसगढ़ की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस को आईना दिखाए। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने घोषणापत्र में 316 वादे किए। जिनको राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए प्रारंभ की थी। छत्तीसगढ़ के लाखों किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए, लेकिन राज्य सरकार ने उस सूची का सत्यापन नहीं किया। जिस वजह से आज छत्तीसगढ़ के उन लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सालाना 6 हजार रुपये नहीं मिल पा रहे हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष तक हमारी सरकार थी, तो चरण पादुका और साड़ी वितरण योजना चल रही थी। लेकिन उस योजना को रोक दिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रह के काम में जो दिन तय होते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा कम किया गया। तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाला बोनस कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं दिया गया। यही कारण रहा कि वहां तेंदूपत्ता संग्रहण विगत 5 वर्षों में लगभग 4 लाख बोरी कम हुआ। पात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी विधेयक भाजपा सरकार लेकर आई थी। उसका उद्देश्य हमारे जनजातीय बंधुओं की संस्कृति और विचारों को संजोकर रखना था। लेकिन कांग्रेस सरकार हमेशा इस बिल के विरोध में रही और धर्मांतरण को लगातार बढ़ावा दे रही है। केवल इतना ही नहीं कांग्रेस सरकार तो वहां नक्सलियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं को अवरुद्ध कर दिया। कांग्रेस धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ खड़ी थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा दिया है।

प्रमुख समाचार

न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका के संदर्भ में राय मांगी

नईदिल्ली। बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका में शामिल कानूनी मुद्दों पर मंगलवार को महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से राय मांगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले महेश श्रीश्रीमल ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में राहुल गांधी की ''कमांडर-इन-थीफ'' टिप्पणी पर मानहानि की शिकायत दर्ज की। गांधी द्वारा निचली अदालत के समन को चुनौती देने के बाद, उच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया। तब से, उच्च न्यायालय के समक्ष गांधी की याचिका पर सुनवाई समय-समय पर स्थगित होती रही। मंगलवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.वी. कोटवाल ने कहा कि याचिका में ''कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न'' उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, ''इसलिए, मैं महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से इस मामले से जुड़े सभी कानूनी मुद्दों पर अदालत की सहायता करने का अनुरोध करना जरूरी समझता हूं।''

भाजपा की सूची पर विपक्ष का वार, शिवराज का पलटवार

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची में सात सांसदों को विधानसभा के नाम शामिल हैं जिनमें तीन केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसको

लेकर अब सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सहित विपश्री दलों ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज के काम और नाम से 15 दिन पहले अमित शाह जी और अब मोदी जी कन्नी काट गए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उन्होंने कल स्वीकार कर लिया कि उनके पास चुनाव लड़ाने योग्य उम्मीदवार भी नहीं है। जिस पार्टी के पास विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नहीं बचे वह अनर्गल बातें कर रही है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में कुछ चीजें मरम्मत के परे हो चुकी हैं। जिन मंत्रियों के नाम सूची में हैं उन्होंने शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा की उनके नाम सूची में होंगे। उन्होंने कहा कि अगर सूची देखेंगे तो 5-6 मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो सूची में दिख जाएंगे। जमीनी हक़ीक़त बता रही है कि भाजपा का कोई भी फॉर्मूला सफल नहीं हो रहा है।

भाजपा मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चिंतित है : दिग्विजय

नईदिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में तीन केंद्रीय मंत्रियों और कुछ सांसदों को मैदान में उतारने का भाजपा

का कदम उसकी संभावनाओं को लेकर चिंता की भावना को दर्शाता है। सिंह ने दावा किया कि राज्य के लोगों ने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है, जो विधायकों को खरीदकर बनाई गई थी। उन्होंने कहा, लोग बहुत गुस्से में हैं और वे इस बार मध्य प्रदेश में बहुमत वाली कांग्रेस सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। सिंह कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भाग लेने के लिए ओरछा में थे। जब उनसे भाजपा द्वारा तीन केंद्रीय मंत्रियों और चार अन्य सांसदों को टिकट देने के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा, ''भाजपा आगामी चुनावों में डर महसूस कर रही है।''कांग्रेस की तुलना जंग लगे लोहे से करने संबंधी मोदी के बयान के बारे मे पूछे जाने पर उन्होंने कहा, '' कभी-कभी, उनके भाषण का स्तर इतना निम्न होता है कि इससे उनके पद से जुड़ी गरिमा और मर्यादा कम हो जाती है।

जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता था

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम के प्रस्तावों को संसाधित करने और

अधिसूचित करने में केंद्र की देरी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में देरी को चिह्नित किया। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि 26 न्यायाधीशों का स्थानांतरण और यहां तक ??कि एक संवेदनशील उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी लंबित है। न्यायमूर्ति कौल ने नियुक्ति के बैकलॉग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नवंबर 2022 से उच्च न्यायालयों द्वारा 70 नाम भेजे गए हैं, लेकिन वे हम तक नहीं पहुंचे हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं क्योंकि रिक्तियां एक बड़ा मुद्दा है। पिछले सात महीनों से हमें कोई नाम नहीं मिला है। सिफारिशें की जाती हैं, और फिर उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता है।

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को पड़ा दिल का दौरा

नईदिल्ली। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया।

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि उन्हें शाम करीब साढ़े चार बजे भर्ती कराया गया। डॉक्टर जलील पारकर के मुताबिक शाहनवाज हुसैन को दिल का दौरा पड़ने के कारण लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सूत्रों ने कहा कि एंजियोप्लास्टी डॉ जलील पारकर की देखरेख में की गई है। हुसैन की हालत अब ठीक है, वह फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। हुसैन बिहार में भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वह राज्य में एनडीए सरकार के दौरान बिहार के उद्योग मंत्री थे। वह अटल बिहार वाजपेयी के मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्रियों में से एक थे। भाजपा नेता ने वाजपेयी सरकार के दौरान राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कोयला मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्री और कपड़ा मंत्री सहित कई विभाग संभाले।

बिखरा विपक्ष नहीं दे पाएगा भाजपा को चुनौती

अभय कुमार दुबे

2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को तीन सवालों का जवाब तलाशना है। क्या वे उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि विपक्षी गठजोड़ भाजपा का विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर दे सकता है? दूसरे, क्या वे एक बार फिर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पिछड़े वर्ग की एकता का वैसा ही गुलदस्ता पेश कर पाएंगे जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया था? तीसरे, उन्हें यह पूर्वानुमान भी लगाना है कि मायावती का रुख क्या होता है। जाहिर है कि अगर मायावती ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो केवल कांग्रेस से गठजोड़ के दम पर उनके लिए भाजपा को रोकना मुमकिन नहीं होगा। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने के सिलसिले में उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वे किसी गठजोड़ पार्टनर को सीटें देने में कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा का चुनाव एक बड़ी लड़ाई है, और छोटी-छोटी बातों से उसे गड़बड़ाया नहीं जा सकता। जाहिर है कि उनके इस वक्तव्य से विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को बहुत तसल्ली हुई होगी।

इस वक्तव्य का सकारात्मक संदेश न केवल कांग्रेस को मिला होगा, बल्कि गठजोड़ से बाहर बैठी हुई मायावती को भी गया होगा. अब मायावती को केवल विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार रहेगा। अगर वहां कांग्रेस ठप्पे के साथ जीतती है तो विपक्षी एकता को जो उछाल मिलेगा, उसमें मायावती अपना फायदा भी देख सकती हैं। हालांकि भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि मायावती विपक्ष के साथ न जा पाएं, लेकिन अगर मायावती ने इस तरह का मन बनाया तो भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। सपा की वोट प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी सफलता दस साल बाद 2022 में सामने आई जब इसने विधानसभा चुनाव में अपने इतिहास में सर्वाधिक 32.06 प्रतिशत वोट हासिल किए। यह अलग बात है कि अपने सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन और सीटों की सम्मानजनक संख्या के बावजूद वह सरकार बनाने से काफी दूर रह गई। सपा ने अपने तीन दशक लंबे वजूद में और भी कई चुनाव लड़े हैं। 2022 के आंकड़े समाजवादी पार्टी के आज तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की विडंबनापूर्ण कहानी कहते हैं। 32.06 प्रतिशत वोटों के समर्थन की सामाजिक रचना पर यादव और मुसलमान वोटों का असाधारण ध्रुवीकरण बेतहाशा हावी दिखता है। कुर्मी-कोइरी और अन्य पिछड़ी जातियों के भी सम्मानजनक वोट मिलते हुए दिखते हैं।

स्पष्ट है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ यह पहला विधानसभा चुनाव रणनीतिक दृष्टि से अंशतः सफल होते हुए भी लक्ष्य से बहुत दूर (सिर्फ 111 सीटें) रह गया। अखिलेश ने पिछड़ी जातियों का एक गुलदस्ता तैयार करने में कामयाबी हासिल की, और मुसलमान वोटों के भीतर मौजूद किसी भी तरह के ढुलमुलपन को भी खत्म करके उनका सर्वांग समर्थन जीत लिया लेकिन वे भाजपा की राज्य सरकार से ब्राह्मण समुदाय की नाखुशी, सरकार द्वारा खुल कर चलाए जा रहे ठाकुरवाद, कोविड महामारी के दौरान हुई बदइंतजामी, किसान आंदोलन से बनी पश्चिमी उ.प्र. की नाराजगी और आवारा पशुओं से किसानों को होने वाली समस्याओं का कोई लाभ नहीं उठा पाए। सरकार के खिलाफ एक ठीकठाक किस्म की 'एंटीइनकम्बेंसी' थी जो इन सभी पहलुओं को मिला कर देखने पर सीएसडीएस-लोकनीति के चुनाव-उपरांत सर्वे में साफ दिखाई देती है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, भूमिहार और जाटों के वोटों के मामले में अपने पिता द्वारा सपा की तरफ खींची गई उस सामाजिक संरचना को दोहराने में विफल रही. इसी के दम पर अखिलेश 2012 में मुख्यमंत्री बने थे। इसका दूसरा बड़ा कारण यह कि भाजपा अपने वोटों को 2017 में अगर 39.65 प्रतिशत तक ले गई थी, तो 2022 में एंटीइनकम्बेंसी के बावजूद उसके वोट इससे भी ज्यादा बढ़ कर 41.29 पर पहुंच गए। यानी, हिंदुत्ववादी बहुसंख्यकवाद की गोलबंदी ने तीस प्रतिशत के आसपास वोट प्राप्त करके बहुमत हासिल करने की परंपरा को अतीत की वस्तु बना दिया। इस लिहाज से जातियों के बहुसंख्यकवाद की राजनीति ने भी इस चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाया।

कांकेर में बड़ी नक्सली साजिश, सर्चिंग में मिला तीन किलो का आईईडी

कांकेर। कांकेर में एक बार फिर जवानों को नक्सल मोर्च पर बड़ी सफलता मिली है। इस बार जवानों की मदद ग्रामीणों ने भी की। गुमड़ीडीही और बड़गांव रोड से गुजर रहे लोगों ने एक टिफिन देखा। ग्रामीणों को इसमें नक्सली साजिश नजर आई। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। दलबल के साथ दुर्गुकोंदल पुलिस और बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची।

नक्सली हर साल 21 सितंबर से 28 सितंबर के बीच स्थापना सप्ताह मनाते हैं। अभी स्थापना सप्ताह जारी है। इस बीच नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। इसी को देखते हुए पुलिस और सुरक्षाबल के जवान हाई अलर्ट पर है और लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। दुर्गुकोंदल थाना क्षेत्र अंतर्गत कोंडे गांव के स्टेट हाइवे 25 में एक डिब्बा दिखने की सूचना मिली। मौके पर दुर्गुकोंदल पुलिस पहुंची और डिब्बे की जांच की तो पता चला कि उसमें नक्सलियों ने आईईडी रखा हुआ

है। 3 किलो का आईईडी टिफिन में रखा हुआ था। पखांजूर की बीडीएस टीम को बुलाया गया और आईईडी को वहीं डिफ्यूज किया गया है।

एडिशनल एसपी प्रशांत शुक्ला ने कहा ग्रामीणों की सूचना पर दुर्गुकोंदल पुलिस पहुंची। सर्चिंग के दौरान 3 किलो का आईईडी मिला। बीडीएस की टीम ने आईईडी को रिफ्यूज कर दिया है।आसपास के इलाकों में सघन सर्चिंग की जा रही है।

उत्तर बस्तर कांकेर जिले की बात करे तो पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 साल में सुरक्षा बलों ने 146 आईईडी बरामद किया है। साल 2020 में सबसे ज्या 88 आईईडी बरामद किया गया था। साल 2021 में यह संख्या घटकर 30 पहुंच गई। साल 2022 में सिर्फ 9 आईईडी बरामद कर जवानों ने नष्ट किया। 3 साल में आईईडी की चपेट में आने से 12 से ज्यादा जवान जख्मी हुए। एक ग्रामीण की जान गई। सबसे ज्यादा आईईडी कोयलीबेड़ा और अंतागढ़ ब्लॉक के जंगल और सड़क किनारे से बरामद किया गया है। कहीं टिफिन बम तो कहीं पाइप बम जवानों ने बरामद किया है।

शासन और सामुदायिक सहभागिता से अमरकोट अब पेयजल की समस्या से मुक्ति की ओर

- **जल जीवन मिशन के तहत गांव के 357 घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित**

महासमुंद। जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व महासमुंद जिले के अमरकोट गांव में पानी की बहुत समस्या थी। लोगों को बहुत दूर से पीने का पानी लेने जाना पड़ता था। हैंडपंप में पानी का स्तर भी बहुत कम था, वहां पर महिलाओं एवं वृद्ध जनों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता था। जल जीवन मिशन के कार्य के दौरान ग्राम अमरकोट में स्वैच्छिक संगठन और ग्रामीणों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसके तहत गांव में जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया एवं एटीके टेस्ट के लिए जल वाहिनियों की समिति का गठन किया गया। जिसके फलस्वरूप गांव के 357 घरों में शुद्ध और पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। अमरकोट गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचाने के साथ ही लोगों को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भी जागरूक किया गया है।

वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम अमरकोट में लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। इस मिशन के तहत टंकी निर्माण एवं पाइप लाइन के द्वारा घर-घर में स्टैंड पोस्ट बनाकर नल कनेक्शन दिया गया। जिससे सभी ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है । जलवाहिनी समिति द्वारा साल में दो बार जल का परीक्षण किया जाता है । समिति के पास जल स्त्रोत के आस पास साफ-सफाई, रखरखाव की भी जिम्मेदारी होती है और जल जनित बीमारियों के बारे में लोगों को अवगत भी करते है।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया है। इस समिति में 16 सदस्य हैं, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है और 25 प्रतिशत पंचायत सदस्यों का एवं 25 प्रतिशत गांव के आदिवासी जन एवं अधिमान्य लोग शामिल हैं। इनका काम आपूर्ति से संबंधित योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना है तथा प्रचालन तथा रख-रखाव के साथ-साथ निगरानी और चौकसी से संबंधित कार्य करना है। यह समिति की ओर से तकनीकी और वित्तीय सहायता संबंधी रिपोर्ट बनाते हैं ताकि संसाधनों और योजनाओं की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा सकें।

गणेश विसर्जन-झांकी 28 की रात में निकलेगी

- **सुबह निकलेगा ईद-ए-मिलाद -उन-नवी का जूलूस**
- **प्रशासनिक अफसरों ने ली शांति समिति की बैठक**

राजनांदगांव। ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नवी) एवं गणेश विसर्जन/झांकी त्यौहार को आपसी भाई चारे व सौहार्द पूर्ण तरिके से मनाये जाने हेतु गणमान्य नागरिक जन प्रतिनिधि एवं विभिन्न सामाजिक/धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों का शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम स्थित जनसंवाद कक्ष में ली गई। बैठक में प्रतिनिधियों से गणेश विसर्जन/झांकी एवं ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नवी) के संबंध मे विस्तार से चर्चा की गई। 27 सितंबर को रात्रि से शहर के मार्गो में लगे गेट/लाईटिंग-झालर निकलवा देवें, और 28 सितंबर को नगर निगम द्वारा सड़क की साफ-सफाई सुनिश्चित हो जावेगी, 28 सितंबर को प्रातः से संध्या 5 बजे तक कोई गणेश विसर्जन शहर में ना निकाले ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नवी) का जूलूस 28 सितंबर को प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक शहर में निकाला जायेगा और रात्रि 7 बजे के बाद गणेश झांकी शहर के विभिन्न चौक चौराहो से होते हुए निर्धारित मार्ग से निकाली जायेगी।

बैठक में शहर के गणमान्य नागरिक जन प्रतिनिध एवं विभिन्न सामाजिक/धार्मिक संगठन एवं उपस्थित शासन व प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आम सहमती से तय किया गया कि ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नवी) जूलूस एवं गणेश विसर्जन/झांकी प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। पुलिस कप्तान राहुल देव शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र के गणेश विसर्जन/झांकी एवं ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नवी) समिति के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाएं। ताकि यातायात आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। गणेश विसर्जन/झांकी एवं ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नवी) जूलूस के दौरान यातायात बाधित न हो इसका पूर्ण रूपेण ध्यान रखें, आम जन से भी अपील किया जाता है कि वे पूर्ण श्रद्धा के साथ सभी धर्मा का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण एवं गरिमा से आपसी भाई चारे एवं सौहार्द पूर्ण तरिके से त्यौहार मनावे साथ ही यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था में राजनांदगांव पुलिस को सहयोग प्रदान करें।

चेरपल्ली में मेरी माटी मेरा देश-अमृत कलश यात्रा का आयोजन

बीजापुर। भोपालपटनम विकास खंड अंर्तगत ग्राम चेरपल्ली में मंगलवार को चेरपल्ली कैंप में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बी/170 बटालियन के कमांडेंट किशोर कुमार के निर्देश अनुसार चेरपल्ली में देश के लिए शहीद वीर-वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा अभियान का आयोजन ग्राम पंचायत चेरपल्ली में किया गया। यह अभियान 16 अगस्त 2023 से आरंभ हुआ है, जो देश के हर ब्लॉक नगर निगम, ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित ग्राम वासियों एवं सशस्त्र बल बी/170 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के द्वारा पंचप्राण का शपथ भी लिया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि गांव के सामान्य व्यक्ति को देश की माटी के महत्व को बताते हुए देश के माटी से जोडऩा है, भारत के वीर सपूतों को आजादी के मौके पर याद करना तथा उनकी स्मृति अमृत सरोवरों की नजदीक ग्राम पंचायत में (शिला पलकाम) स्मारक स्थापित करना है। इस अभियान के दौरान देशभर में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण देश के हर कोने से एकत्रित की गई मिट्टी को लेकर कलश देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी, जिससे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास मिट्टी और पौधों को मिलाकर अमृत वाटिका बनाई जाएगी, मिट्टी का नमन और वीरों का वंदन मेरी माटी मेरा देश अभियान के प्रमुख घटक है।

उक्त अभियान में मनोज कुमार सहायक कमांडेड, निरीक्षक जीडी कुशलप्पा समवाय अधिकारी बी/170 बटालियन, भोपालपटनम थाना प्रभारी जयकुमार साहू, ग्राम पंचायत सचिव निम्मैया तलांडी, ग्राम पंचायत चेरपल्ली के सरपंच दशरथ वासम, तथा ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासी पंचगण तथा ग्राम पटेल, चेरपल्ली के समस्त ग्रामीण उपस्थित थे।

प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करें श्रमिक संघ प्रतिनिधि : एसईसीएल

कोरबा। साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड एसईसीएल की संचालन समिति की बैठक में उत्पादन व उत्पादकता के साथ ही कर्मचारियों के सुरक्षा, सीआईएल द्वारा जारी आश्रित रोजगार एवं स्थानांतरण के एसओपी पर मंथन किया गया। इस दौरा प्रबंधन ने आगामी पांच अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने का आह्वान श्रमिक संघ प्रतिनिधियों से किया।

समिति की बैठक की अध्यक्षता एसईसीएल सीएमडी डा प्रेम सागर मिश्रा ने की। इस दौरान एसईसीएल निदेशक मंडल से निदेशक तकनीकी संचालन एसके पाल, निदेशक वित्त जी श्रीनिवासन, निदेशक योजना-परियोजना एसएन कापरी, निदेशक कार्मिक देबाशीष आचार्या एवं एसईसीएल संचालन समिति से हरिद्वार सिंह एटक, मजरुल हक अंसारी बीएमएसए गोपाल नारायण सिंह एसईकेएमसी, वीएम मनोहर सीटू, एके पांडे सीएमओ,आई व विभिन्न विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ में कोल इंडिया कार्पोरेट गीत बजाया गया व कार्य के दौरान दिवंगत श्रमवीरों को मौन श्रद्धांजली दी गई। इसके साथ ही सभी सदस्यों दवारा सुरक्षा शपथ ली। तत्पश्चात पिछली संचालन समिति की बैठक के कार्यवृत का पुष्टिकरण एवं बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में चर्चा की गई।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सीएमडी डा मिश्रा ने कहा कि संवेदनशील और संवादशील प्रबंधन हमारे कार्य संचालन का आधार है और यह हमारी प्राथमिकता भी है। विदित हो कि एसईसीएल प्रबंधन द्वारा भूविस्थापितों को हितों के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में एसईसीएल द्वारा रिकार्ड 704 भू-स्वामियों को रोजगार प्रदान किया है जो कि कंपनी के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। इस वित्तीय वर्ष में भी अप्रैल से जुलाई तक की अवधि में 250 से अधिक परियोजना प्रभावितों को रोजगार स्वीकृति दे दी गयी है व ज्यादा भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों के निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। बैठक के अंत में सीएमडी डा प्रेम सागर मिश्रा, निदेशक मंडल एवं संचालन समिति के सदस्यों द्वारा निदेशक तकनीकी संचालन एसके पाल का शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। ज्ञात हो कि पाल इसी महीने कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

मुर्गे के शिकार के चक्कर में लोहे की तार में फंसा तेंदुआ

कांकेर। शहर से सटे सिंगारभाट गांव में बीच बस्ती में तेंदुआ घुस आया। घटना मंगलवार सुबह करीब 4 बजे की है। जब पहाड़ी से उतरकर एक तेंदुआ खाने की तलाश में गांव में घुस गया। इस दौरान गांव में बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं थी लेकिन मुर्गे मुर्गियां बांग देकर लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी तेंदुए ने उन पर हमला करने की कोशिश की। मुर्गे मुर्गियां तो भाग गए लेकिन भूखा तेंदुआ इस दौरान एक घर के आंगन में रखे लोहे की तार में फंस गया। तार में फंसने के बाद तेंदुए ने अपने आप को उस तार से निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन तेंदुआ उसमें से निकल नहीं पाया। लोहे की तार में फंसे रहने और उससे निकलने की नाकाम कोशिश के दौरान तेंदुआ बुरी तरह से घायल हो गया। गांव के लोगों ने जैसे ही तेंदुए को देखा गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना सरपंच ने वन विभाग को दी। गांव में तेंदुआ घुसने की खबर फैलते ही काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। जिससे तेंदुए के रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी। पुलिस बल को भी मौके पर बुलाया गया।

जगदलपुर के किलेपाल स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग

जगदलपुर। जगदलपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर किलेपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार सुबह आग लग गई। आग मेडिसिन स्टॉक रूम में फैली।जिसके कारण मेडिसिन रूम में रखी दवाईयां और अन्य सामान जलकर राख हो गया।इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई।आग लगने की खबर जैसे ही लगी वैसे ही अस्पताल को खाली करवाया गया। जिस वक्त आग लगी, उस समय हॉस्पिटल में 25 मरीज भर्ती थे। जिसके कारण उनके परिजनों में दहशत का माहौल देखने को मिला। आगजनी के खबर लगते ही कोडेनार थाना के पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां जगदलपुर से रवाना की गई। जगदलपुर शहर के किलेपाल 45 किलोमीटर दूर होने के कारण गाड़ियां काफी लेट से पहुंची। लेकिन 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आगजनी शार्ट सर्किट की वजह से हुई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पुलिस नुकसान का आंकलन कर रहे हैं।

विधानसभा निर्वाचन के लिए अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

मोहला। विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा निर्वाचन में लगे सेक्टर, जोनल, ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मोहला में आयोजित किया गया। जिसमे अधिकारियों को ईव्हीएम, वीवीपेट मशीनों के संचालन, विभिन्न गतिविधियों, बरती जानी वाली सावधानियों का अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान मशीनों में टैक लगाने, संचालन करने, चालू करने, बंद करने, मॉकपोल, वास्तविक मतदान कराने आदि सभी पहलुओं की भलीभाती प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में आदर्श आचार संहिता, ईव्हीएम मशीन के संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सेक्टर तथा नोडल अधिकारियों के कर्तव्य तथा ईव्हीएम मशीन के संचालन प्रक्रिया को डेमो के जरिए संचालित कर दिखाया गया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्रभारी श्री हेमंत ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर श्री अविनाश ठाकुर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री धर्मेन्द्र शारस्वत एवं श्री सईद कुरेशी उपस्थित थे।

चिर्रा एवं कुदमुरा में खुलेंगे नवीन धान उपार्जन केंद्र

कोरबा। शासन द्वारा ग्रामीणों-कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीफविपणन वर्ष 2023-24 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए निम्नानुसार स्थान में नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोले जाने की अनुमति प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत कोरबा जिले के अनुसूचित क्षेत्र ग्राम चिर्रा में एवं ग्राम कुदमुरा में नवीन धान उपार्जन केंद्र संचालित किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोले जाने हेतु विभिन्न आवश्यक कार्यवाही किया जाना है। जिन स्थानों पर मंडल/उपमंडी प्रांगण उपलब्ध है उनका उपयोग धान खरीदी हेतु किया जाए। धान खरीदी हेतु ऐसे स्थान चयन किया जाए, जहां पर्याप्त समतल एवं ऊंची भूमि उपलब्ध हो। नीची अथवा गड्ढे वाले भूमि का चयन न किया जाए। उपार्जन केन्द्रों के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं अन्य स्टॉक की व्यवस्था समितियों द्वारा की जायेगी। नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोलने हेतु कम्प्युटर सेट्स दो प्रिंटर, यू.पी.एस. 2 केव्हीए जनरेटर की व्यवस्था विपण संघ द्वारा की जाए।

विधानसभा निर्वाचन के दौरान वीडियोग्राफी कार्य हेतु निविदा 06 अक्टूबर तक आमंत्रित

कोरबा। वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतर्गत विधानसभा आगामी निर्वाचन 2023 के लिए कोरबा जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण, उड़नदस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दल, नामांकन कार्यवाही, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र, मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों में वीडियोग्राफी किए जाने हेतु पंजीकृत तथा अनुभवी संस्थाओं, फर्मों से प्रति 8 घंटे प्रति कैमरा प्रति दिन के दर निर्धारण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2023 को अपरान्ह 03 बजे तक और निविदा खोलने की तिथि 6 अक्टूबर 2023 को अपरान्ह 4 बजे खोली जाएंगी। इच्छुक निविदाकर्ता जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्टर एवं (निर्वाचन शाखा) कोरबा से 1000 (एक हजार रूपये मात्र) नगद राशि अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क जमा कर 06 अक्टूबर 2023 दोपहर 02 बजे तक जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है।

जीपीएम में पीडीएस के तहत मिलने वाले चावल का संकट

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिले में पीडीएस के तहत हितग्राहियों को मिलने वाले चावल का संकट सामने आया है। नागरिक आपूर्ति निगम के वेयरहाउस गोदामों में चावल के स्टॉक की शार्टेज हो गई है। गोदाम में अभी केवल अक्टूबर महीने के लिए ही चावल बचा है। जबकि शासन के नियमानुसार, वेयरहाउस में कम से कम 3 माह का चावल होना चाहिए। लेकिन जिले में संचालित राइस मिलरों द्वारा धीमी गति से चावल जमा किया जा रहा है, जिसके चलते ही यह समस्या जिलेवासियों के सामने आई है।

दरअसल, जिले में संचालित राइस मिल के द्वारा अभी तक 17634।86 मीट्रिक टन चावल जमा नहीं किया है। इनके द्वारा केवल 73।30 फीसदी ही चावल जमा किया गया है। आज की स्थिति में नान गोदाम में केवल अक्टूबर माह का चावल

भंडार है, बाकी नान के गोदाम खाली हैं। जिले के राइस मिलों ने चावल जमा नहीं कराने की वजह से पूरी स्थिति बिगड़ी है। नान डीएम से बात करने पर उनका कहना है कि मिलर के चावल जमा नहीं करने से पीडीएस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो चावल की अन्य जिले से व्यवस्था कर वितरण किया जाएगा। जिला विपणन अधिकारी रमेश लहरे ने बताया, कुछ राइस मिलर्स द्वारा 50 फीसदी से कम चावल जमा किया गया है। कुछ राइस मिलर द्वारा संतोषजनक चावल जमा किया गया है। लेकिन 50 फीसदी से कम चावल जमा करने वाले राइस मिलों को नोटिस दिया गया है। अगर समय पर उनके द्वारा चावल जमा नहीं किया गया, तो उस स्थिति पर बैंक गारंटी की राशि को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी।

जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने कहा दो दिनों पहले कलेक्टर द्वारा राइस मिलर्स की मीटिंग ली गई थी। कड़ी चेतावनी दी गई है अगले 3 महीने का चावल गोदाम में भंडार रहना अनिवार्य है यह नियम है राइस मिलर्स की चावल जमा की गति धीमी होने के कारण भंडारण में अंतराल आ गया है। मिलर्स के द्वारा चावल जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई थी। लेकिन अब चावल जमा करने की समय सीमा एक माह बढ़ा दिया गया है। अब 31 अक्टूबर तक मिलर चावल जमा कर सकते हैं। यदि चावल जमा करने की तारीख नहीं बढ़ती है, तो इतने कम समय में बचे हुए चावल के स्टॉक को जमा करना संभव नहीं दिख रहा है। अब देखना यह है तय समय सीमा तक राइस मिलर शेष चावल जमा करते हैं या नहीं। जानकारी के अनुसार, जिले में संचालित राइस मिलरों के द्वारा कुल जमा किये गए चावल में भुआजी फर्म प्राइवेट लिमिटेड 38.12, शिवानी ट्रेडर्स 53.09, यश राइस मिल 53.03, यश मॉर्डन फूड 56.30, मां नर्मदा राइस प्रोडक्ट 57.73, श्याम इंडस्ट्रीज 62.06, श्याम फूड प्रोडक्ट 64.72, मेजर्स दक्ष फूड 71.68, केसरवानी राइस मिल 75.84, मेजर्स वंदना राइस 80.58, जेपी अग्रवाल एंड सन कोल्ड स्टोरेज 82.07, बालाजी फूड 82.41, श्री साइन एग्रो 82.87, मां नर्मदा एग्रोटेक 82.87, जेपी अग्रवाल एग्रोटेक 87.29, गर्ग फूड प्रोडक्ट 89.02, लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्री ने 9.64 फीसदी चावल जमा किया है।

कोरबा-कुसमुंडा रोड पर जाम के खिलाफ 2 को माकपा करेगी विरोध प्रदर्शन

कोरबा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरबा-कुसमुंडा मार्ग पर आम नागरिकों की आवाजाही को सुलभ बनाने की मांग की है। इस संबंध में एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर सड़क सत्याग्रह करने की चेतावनी दी गई। माकपा के इस आंदोलन को सीटू ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि कोरबा-कुसमुंडा के बीच फोर-लेन सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। सर्वमंगला चौक से कुसमुंडा तक कोयला परिवहन के लिए एसईसीएल की भारी वाहनें बेतरतीब ढंग से खड़ी रहती है, जिसके कारण जाम होने के साथ यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। माकपा ने अपने ज्ञापन में बताया है कि हालत इतनी खराब है कि स्कूली बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई मरीज जाम में घंटों फंसे रहते है और कई बार डिलेवरी पेशेंट की स्थिति चिंताजनक बन चुकी है।

कुछ दिन पहले ही कलेक्टर ने एसईसीएल व परिवहन अधिकारियों को यातायात सुव्यवस्थित करने और बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही के निर्देश भी दिए थे। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने आरोप लगाया है कि एसईसीएल प्रबंधन और परिवहन अधिकारियों की मिली भगत के कारण कलेक्टर के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। एसईसीएल आम जनता के जीवन को जोखिम में डालकर केवल मुनाफा कमाने में लगा है। माकपा ने मांग की है कि आम जनता की सुविधा के लिए एक लेन सुरक्षित किया जाए, जिसमें भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित हो।

मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही किया जाएगा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही किया जाएगा, नवा रायपुर में व्यापरियों को 945 के स्थान पर 540 प्रति वर्गफीट की दर से भूखण्ड दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न संस्था व समाज के लोगों को आबंटित भूमि में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित् अधिकतम की जाएगी।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रूपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया। ग्राम डूण्डा, सेजबहार एवं बोरियाकला, तहसील व जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास एवं प्रभावितों को प्लाट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया जाए। न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए। कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों का योजना से पृथक करने हेतु डिनोटिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रभावितों को भूखण्ड प्रदान किया जा सके।

नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आबंटन दर एवं भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में व्यापरियों को 945 रूपए के स्थान पर 540 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से भूखण्ड दिया जाएगा। इससे नवा रायपुर प्राधिकरण को होने वाली क्षति की कुल राशि 117.86 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया।

जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 03 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (वेतनमान 118500-214100) सृजित करने का निर्णय लिया गया। राजगामी संपदा की भूमि वाईडनर मेमोरियल स्कूल हेतु भूमि का आबंटन करने का निर्णय लिया गया। रत्नेश्वर कुर्मि क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर को शासकीय भूमि आबंटन और व्यवस्थापन में रियायत का निर्णय लिया गया। आवेदक संस्था अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज भिलाई-दुर्ग को आबंटित भूमि में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। गोंड समाज जिला-सरगुजा को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

रजवार समाज सूरजपुर को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। दल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव द्वारा सामाजिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तहसील साहू संघ छुरिया, जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। हरदिया साहू समाज रायपुर और साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1959 के पूर्व के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। ग्राम पंचायत घुमका, जिला- राजनांदगांव को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत पोरथा, जिला-सक्ती को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में श्री सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट, जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को होम लोन के ब्याज पर मिलेगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के पत्रकारों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। पत्रकार अब किफायती दर पर अपने घर का सपना पूरा कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा पर अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग की तरफ से श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना पत्रकारों के लिए लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख रुपये तक के होम लोन के लिए 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 साल तक दिया जाएगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 के बाद से खरीदे गए मकान पर प्रभावशील रहेगी। इस योजना का लाभ सिर्फ हाउसिंग लोन पर दिया जाएगा। खरीदा जाने वाला मकान छत्तीसगढ़ के अंदर होना चाहिए। ब्याज पर सब्सिडी 30 लाख रुपये तक के हाउसिंग लोन पर मिल सकेगा। नेशनल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नोटिफाइड वित्तीय संस्थानों और सहकारी बैंकों से लिए गए हाउसिंग लोन पर हर महीने 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 साल तक दिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

पहली नवंबर से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी

रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी एक नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी।मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित् अधिकतम की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

राज्य स्तर पर अक्टूबर में होगा सीनियर व जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर व छत्तीसगढ़ प्रदेश आरचरी एसोसिएशन के द्वारा राज्य स्तरीय सीनियर व जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से शुरु होने जा रहा है। 2 अक्टूबर को सीनियर व 9 अक्टूबर को जूनियर स्तर के प्रतिभागी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश आरचरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश मुरारका ने बताया कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन राजधानी रायपुर में स्थित आउटडोर स्टेडियम बुढ़ातालाब में राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा। इसी प्रकार राज्य स्तरीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 9 अक्टूबर को महासमुंद जिले के बागबाहरा में स्थित स्वागमी आत्मानंद स्कूल के परिसर में सुबह 10 बजे से शुरु होगा।

छत्तीसगढ़ में सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है भाजपा!

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 करीब है। सभी सियासी दल टिकट वितरण के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। इस बीच सियासी गलियारे में यह चर्चा तेज हो चली है कि भाजपा प्रदेश के अपने सभी सांसदों को इस विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इस बीजेपी के इस फैसले को चुनावी मास्टरस्ट्रोक की तरह देखा जा है। जो कही न कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है।

सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सांसदों को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। रायपुर उत्तर सीट से सांसद सुनील सोनी चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बेलतरा विधानसभा से टिकट देने की चर्चा है। कवर्धा से सांसद संतोष पांडेय को बीजेपी टिकट दे सकती है। रायगढ़ सांसद गोमती साय को बीजेपी नंदकुमार साय के खिलाफ उतार सकती है। महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू को महासमुंद या खल्लारी से विधानसभा चुनाव में मौका मिल सकता है। सारंगढ़ सांसद गुहाराम अजगले का नाम भी सारंगढ़ विधानसभा चुनाव में सामने आ सकता है। दुर्ग सांसद विजय बघेल को पहले ही पाटन से बीजेपी टिकट दे चुकी है। वहीं अभी कांकेर सांसद मोहन मंडावी के नाम को लेकर कोई खबर भाजपा मुख्यालय से सामने नहीं आई है।

बीजेपी के इस दांव से सत्ताधारी कांग्रेस समेत अन्य दल सकते में हैं। सांसदों को दिये जाने वाले सीटों पर कांग्रेस समेत अन्य दलों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि बीजेपी सांसद जिस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, उसके आसपास की सीटों को भी वे प्रभावित करेंगे। जिससे कांग्रेस को सीधा नुकसान हो सकता है। साथ ही आप और जेसीसीजे समेत अन्य दलों को भी नुकसान होगा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर 21 सीटें पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिये हैं। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे और दुर्ग लोकसभा से भाजपा सांसद विजय बघेल को पाटन विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक किसी भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है।

छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का मुख्यमंत्री आज करेंगे लोकार्पण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार विश्वस्तरीय खेल मैदान भी तैयार किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय हाकी स्टेडियम के बाद खेलों के लिए अब एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात रायपुर में टेनिस अकादमी के रूप में प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बुधवार 27 सितंबर को टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी (छात्रावास एवं प्रशासनिक भवन) का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल तथा लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहेंगे। रायपुर के लाभांडी में 17.15 करोड़ रूपए की लागत से तैयार ये टेनिक अकादमी छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी अकादमी होगी।

4 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की गयी टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी को तीन मुख्य हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला भाग एडमिन बिल्डिंग है जो तीन मंजिला है। इसमें रूम, हाल, जिम, वीआईपी लाउंज के साथ ही मीडिया सेंटर के साथ ही 500 की दर्शक क्षमता के साथ अनेक सुविधाएं होंगी। दूसरे हिस्से के रूप में अकादमी की हास्टल बिल्डिंग है। यह भी तीन मंजिला है जिसमें कार्यालय, अधीक्षक रूम, पार्किंग, किचन, डायनिंग जैसी अनेक सुविधाएं होगी। तीसरे हिस्से के रूप में मुख्य स्टेडियम है जहां 2500 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। टेनिस एकेडमी अंतर्गत 1 नग मुख्य टेनिस कोर्ट (सिंथेटिक) एवं 5 नग प्रेक्टिस टेनिस कोर्ट (सिंथेटिक) का प्रावधान किया गया है। टेनिस एकेडमी का निर्माण कुल 4 एकड़ क्षेत्रफल अंतर्गत किया गया है। टेनिस कोर्ट निर्माण हेतु अल्ट्रा कुशन 9 लेयर सिंथेटिक सरफेस उपयोग किया गया है। मुख्य टेनिस कोर्ट की दर्शक क्षमता 2000 एवं मुख्य भवन अंतर्गत व्ही आई पी दर्शक क्षमता 500 रखी गई है। दर्शक बैठक व्यवस्था हेतु स्टेडियम चेयर का प्रावधान रखा गया है।

भाजपा की परिवर्तन यात्रा फ्लाप : मरकाम

- **जनता ने नकार दिया, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है**

रायपुर। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को जनता ने नकार दिया। परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं एकत्रित हो रही। परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं आ रहे है इसलिये अमित शाह भी दंतेवाड़ा में नहीं आये। बाद में भी उसके कार्यक्रम बना रद्द कर दिया। भाजपा की तथाकथित परिवर्तन यात्रा में जो प्रदेश के बाहर के नेता आ रहे है उसके नुक्कड़ सभाओं के बराबर भी भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही। तमाम कोशिशों, लाखों रूपये खर्च करने के बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा फ्लाप हो गयी। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को असफल होना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश में परिवर्तन नहीं चाहती है। उक्त बातें राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वरिष्ठ मंत्री मोहन मरकाम ने कहीं।

उन्होंने कहा कि भाजपा के परिवर्तन यात्रा में 15 दिन में प्रधानमंत्री से लेकर दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए और चले गये इनके आने से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? भाजपा के राजनैतिक यात्रा में सरकारी खर्चे और सुख सुविधा विलासिता उपभोग कर आये केंद्रीय मंत्रियों ने सिर्फ भाजपा का प्रचार-प्रसार किया। जब कोई मंत्री का दौरा होता है तब जनता उस मंत्री से कोई नई सौगात की उम्मीद करती है। उनके विभाग से संबंधित समस्याओं का हल चाहती है जो इन केंद्रीय मंत्रियों के दौरा में कहीं नहीं दिखा। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में प्रधानमंत्री, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री, सहकारिता राज्य मंत्री, बिजली एवं उद्योग राज्य मंत्री, जल शक्ति एवं जनजाति राज्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, आयुष राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, आये थे। इनके आने से छत्तीसगढ़ को क्या मिला? कोई नई घोषणा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में इन्होंने नहीं किया? भाजपा के सांसदों ने भी छत्तीसगढ़ के लिए इनसे कोई मांग नहीं की। प्रदेश की जनता ने अपने हालात में परिवर्तन 2018 में कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। दिसंबर 2018 में रमन सरकार की विदाई के साथ छत्तीसगढ़ में आमूलचूल परिवर्तन आया है। परिवर्तन आ गया है तभी तो 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को भूलने वाली भाजपा अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाने को मजबूर हुई है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता अजय गंगवानी, ऋषभ चंद्राकर उपस्थित थे।

2

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय मुख्य अभियंता
महानदी गोदावरी कछार, रायपुर (छ.ग.)
ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 148086/ निविदा सूचना क्र .17/ वलेलि/2023-24, बेमेतरा दिनांक 25.09.2023
निम्नलिखित कार्यो के लिए दिनांक 17.10.2023 17:30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का नाम - बेमेतरा जिले के विकासखण्ड साजा की सुरही नदी पर बचेड़ी तटबंध कार्य ।

अनुमानित लागत- रू. 230.37 लाख

(दिनांक 01.08.2010 के एस.ओ.आर. तथा संशोधित 22.08.2022 के अनुसार)

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 03.10.2023 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।

नोट:- निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, बेमेतरा
कृते मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग, रायपुर छ.ग.

जी-05699/9

बैज प्रदेश को बताएँ कि केंद्र सरकार ने कब आवास योजना के लिए मना किया?

- **भाजपा प्रदेश महामंत्री शर्मा ने तंज कसा, संगठन में कोई पकड़ है नहीं और रहमोकरम पर अध्यक्ष बने हैं तो हाजिरी लगाने के लिए बेसिर-पैर के बयान दे रहे**

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आवास योजना रोकने के लगाए गए आरोप को सफेद झूठ का पुलिंदा करार दिया है। शर्मा ने चुनौती दी कि बैज प्रदेश को बताएँ कि केंद्र सरकार ने कब इस योजना के लिए मना किया? सच तो यह है कि आज के उपमुख्यमंत्री और तत्कालीन पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पत्र लिखकर मुख्यमंत्री बघेल को प्रधानमंत्री आवास योजना रोकने का दोषी ठहराया था जिसके चलते 8 लाख गरीबों को पक्के आवास की योजना से वंचित होना पड़ा था।

शर्मा ने कहा कि दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज की संगठन में कोई पकड़ है नहीं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहमोकरम पर इस पद तक पहुँच गए हैं तो अपनी %हाजिरी लगाने% के लिए इस तरह के बेसिर-पैर के बयान देते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने के बाद से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अब ऊँचे ख्वाब देखने लगे हैं और इसीलिए इस तरह के निरर्थक बयान देकर खुद को अव्वल साबित करने की मशक्कत कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस जिस तरह बयानबाजी के लिए बैज का इस्तेमाल कर रही है, उससे बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कम, और कांग्रेस के संचार प्रमुख के सहयोगी के तौर पर काम करते ज्यादा नजर आ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि झूठ पर झूठ बोलकर केंद्र की सरकार पर ऊलजलूल आरोप लगाने की जिस गंदी लत से प्रदेश कांग्रेस और भूपेश सरकार के लोग ग्रस्त नजर आ रहे हैं, उस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को एक बार उपमुख्यमंत्री सिंहदेव का रायगढ़ में कहा गया सच सुन लेना था। उनको मुख्यमंत्री बघेल के उस बयान को भी याद करना था, जिसमें मुख्यमंत्री ने 8 लाख गरीबों के आवास के लिए राज्यांश देने से मना किया था कि इस योजना में %प्रधानमंत्री% शब्द जुड़ा है, इसलिए इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार दे। राजनीतिक ओछेपन और गरीब विरोधी मानसिकता का इससे बड़ा शर्मनाक उदाहरण शायद ही देश में कहीं और देखने-सुनने को मिला होगा।उन्होंने कहा कि जिस प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर झूठ बोलकर प्रदेश के कांग्रेस और भूपेश सरकार के लोग प्रलाप कर रहे हैं, उसका एक सच यह भी है कि केंद्र की सरकार की तरफ से लिखीं चिठियाँ सार्वजनिक पटल पर हैं जिसमें 6 जुलाई 2021 को केन्द्रीय कृषि एवं कल्याण ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालय से नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा पत्र, 15 सितंबर 2021 को केन्द्रीय ग्रामीण तथा पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लिखा पत्र, 22 अगस्त 2022 को मंत्रालय के उपमहानिदेशक द्वारा लिखा पत्र शामिल है। इन पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने संज्ञान नहीं लिया था। उल्टे, 15 मार्च 2023 को जनता जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री बघेल से अपने आवास मांगने विधानसभा परिसर में पहुंची तो उनसे चर्चा करने के बजाय भूपेश बघेल ने अपनी पुलिस को आगे करके उन पर बम फिंकवाये जिसमें कई लोग घायल हुए। प्रदेश के 16 लाख लोगों के आवास छीनने के कलंक से वह नहीं बचेगी।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, महासमुन्द (छ.ग.)
Phone No. 07723-223731, E-mail: eephe-mah-cg@nic.in

क्र. 5825/व.ले. लि./ जि.ज.स्व.मि./ का.अ./ लो.स्वा.या. खण्ड / 2023-24 / महासमुन्द दिनांक 22/09/23

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (online) की निविदा आमंत्रित की जाती है।
कार्य का नामः- महासमुन्द जिले के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगल विलेज/ रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत नवीन नलकूप खनन कार्य।

निविदा क्रमांक व दिनांक	सिस्टम निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1	2	3	4
119/22-09-2023	147786	ग्राम बकमा, केसवा, सिंघनपुर रायमुड़ा, परसट्टी, भटगांव, फरफौद, आमाझोला, सराईपाली, भलेसर-1, भलेसर-2 बोड़रा, हुमासा, चिगरौद-1, चिंगरौद-2 तेलीबांधा, धंसुली-1, धंसुली-2, जामपाली, सिंघरुपाली, झालखम्हरीया, सिरगिडी-जामली-1, सिरगिडी-जामली-2, झारा, जोगीडीपा, पतईमाता, मुंगईमाता, कछारडीह उल्बा, अमोरा, कांपा, खम्हारमुड़ा, परसवानी, कोकड़ी एवं खट्टा नल जल प्रदाय योजना अन्तर्गत 35 नग ट्यूबवेल ड्रिलींग कार्य वि.ख. महासमुन्द (प्रथम आमंत्रण)	42.68
120/22-09-2023	147793	ग्राम अमोरी, पंडरीपानी, बनसिवनी, गोंडबहार, लभराकला, लाफिनकला, भुरका, परसकोल, पचपेड़ी, मोंगरा, साल्हेमाठा, पचपेड़ी नवागांव, मधुवन, मोरधा. मुरकी, गुढेलाभाठा, नरतोरा,झिलमिला, पचरी, परसदा-ब परसदा-ख, जिवतरा, मुढ़ीयाडीह, कुल्हरीया, केरामुडा, रामखेड़ा, झाखरमुड़ा, सरेकेल, पाटनदादर, सिंघरुपाली, ओडार, फुलवारी, नवापारा, सिंघनपुर एवं सिंघोड़ा नल जल प्रदाय योजना अन्तर्गत 35 नग ट्यूबवेल ड्रिलींग कार्य वि. ख. महासमुन्द (प्रथम आमंत्रण)	42.68
121/22-09-2023	147794	ग्राम तेंदुवाही, सोरम, परसापाली, उल्बा अलियास, नायकबांधा, सोरिद चोभट्टी, तोरला, सलिहाभाठा, उमरदा, पतेरापाली, मुड़मार, गौरखेड़ा, बनपचरी, चितमाखार, खट्टी सिंघडी, पाली-1, एवं पाली-2 नल जल प्रदाय योजना अन्तर्गत 18 नग ट्यूबवेल ड्रिलींग कार्य वि. ख. महासमुन्द (प्रथम आमंत्रण)	21.95
122/22-09-2023	147796	ग्राम कोसरंगी, झलप, लोहारडीह-1, लोहारडीह-2 लोहारडीह-3, लोहारडीह 4. नांदगांव खरोरा-1, खरोरा-2 बरेकेलखुर्द, मानपुर, जोरातराई, जोबाकला, सिंधौरी, रामपुर मुंगासेर, गोंडपाली, कोना एवं रायतुम नल जल प्रदाय योजना अन्तर्गत 19 नग ट्यूबवेल ड्रिलींग कार्य वि.ख. महासमुन्द (प्रथम आमंत्रण)	23.17
123/22-09-2023	147800	ग्राम बेलर, कल्याणपुर, बांसकाटा, बरबसपुर, अमुरदा, मोहगांव, भोथा, घुंचापाली खर्द गुल्झर, टेंगराही, बिहाझर, चोरभट्टी, बैहाडीह, सेनभाठा, बोकारामुड़ा कला, खसरुपाली (पतेरापाली), केरामुडा खुर्द, कांडीझर, खम्हारमुड़ामाल, छुईहा, फिरगी, सोरदादर, चिंगरीया, पड़कीपाली, ठोंगा, डोंकरपाली, भालुकोना, गबौद, घोईनाबहार, भालुचुवां, हाथीबाहरा, कलमीदादर, पटपरपालीखुर्द, टोंगापानी खुर्द एवं बांदुमुडा नल जल प्रदाय योजना अन्तर्गत 35 नग ट्यूबवेल ड्रिलींग कार्य वि.ख. बागबाहरा (प्रथम आमंत्रण)	42.68
124/22-09-2023	147834	ग्राम खट्टाडीह, कसीबाहरा, कौसरा, कौहाकुड़ा, सेनभाठा, बंजरबाहरा, सिवनीखुर्द बंजारीडीह, द्वारतराखुर्द, खुर्सीपार, खुसरूपाली धौरामठा, आमागांव, टेंगराही, सराईपाली, रिवा, नरतोरी-1, नरतोरी-2, करागुला, बनियातोरा, अमनपुरी, लोंदामुड़ा, पटपरपाली, पंकाडीह, बाम्हनडीह, पोटिया, हिच्छा, झलमला, बैगाखम्हरीया, डोंगाखम्हरीया एवं सिंमगांव नल जल प्रदाय योजना अन्तर्गत 35 नग ट्यूबवेल ड्रिलींग कार्य वि.ख. बागबाहरा (प्रथम आमंत्रण)	42.68
125/22-09-2023	147835	ग्राम छिबर्रा, मातगुड़ा, कस्तुरबोड, सोनदादर (सुनसुईया), केरामुड़ा कला, पेंडराचुर्वा, मातरबाहरा, नवागांव, पलसीपानी, टुहलु, तुपकबोरा, मुडागांव, सुवरमाल -1, सुवरमाल-2, तमोरा, परसापाली, शिकारीपाली, कसेकेरा, बिंद्रावन, सम्हर, बोईरगांव-1, बोईरगांव 2. नर्रा मोहंदी अरंड, जुनवानीकला, देवरी, खम्हरीया-1, खम्हरीया -2 चारौदा, खल्लारी एवं धरमपुर नल जल प्रदाय योजना अन्तर्गत 32 नग ट्यूबवेल ड्रिलींग कार्य वि.ख. बागबाहरा (प्रथम आमंत्रण)	39.02

2. उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। 3. निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 10.10.2023 सायं 6:30 बजे तक तथा निविदा खुलने का दिनांक 11.10.20231

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
महासमुन्द (छ.ग.)

जी-05654/6

आग से खेलते ट्रूडो

दीपक वोहरा

पिछले कुछ दिनों से हम एक समृद्ध व तथाकथित लोकतांत्रिक देश के नेता की गलतियों की शृंखला के गवाह बने हैं। इस नेता का नाम है जस्टिन ट्रूडो, जिनकी पहचान कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में भी है। कहते हैं कि झूठ बोलना कूटनीति पर भारी पड़ सकता है। हरदीप सिंह निज्जर नाम के अपने पसंदीदा खालिस्तान समर्थक आतंकी की, जो पहले एक प्लंबर हुआ करता था और जिसे जून, 2023 में मार गिराया गया था, रक्षा करने में असमर्थता जाहिर करते हुए अपनी संसद में ट्रूडो ने जो बयान दिया है, वह कूटनीति की दुनिया में इतिहास रचने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के विश्वसनीय आरोप (पर, कोई सुबूत नहीं) उनके सामने आए हैं। वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि निज्जर की हत्या कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। अपनी ही संसद में झूठ बोलकर उन्होंने भारी गलती की है। किसी अवांछनीय गतिविधि के सुबूत के बगैर उन्होंने नाम लेते हुए एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया, जिससे उस अधिकारी की जान तक खतरे में पड़ गई। यह भारी चूक है। अपने 50 वर्षों के कूटनीतिक अनुभव में मैंने स्थापित अंतरराष्ट्रीय परंपराओं का ऐसा घोर उल्लंघन होते नहीं देखा। उन्होंने अपनी मूर्खता का एहसास करते हुए अमेरिका में अपने चाचा और अपने पश्चिमी सहयोगियों से भारत के खिलाफ बयान देने की विनती करने की एक बड़ी गलती की। यह बात अलग कि सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा करने के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा रद्द करके भी गलती की, क्योंकि कनाडा को भारत की तुलना में इस एफटीए की ज्यादा जरूरत है। उनकी एक और गलती यह रही कि उन्होंने एक ऐसे उच्चायुक्त को भारत भेजा, जो धैर्य व शांति से व्यवहार करना नहीं जानता और रिपोर्टर के मुंह पर गुस्से से कार का दरवाजा बंद कर लेता है। अभी एक दिन पहले कनाडा में गैंगवार में एक और खालिस्तानी आतंकी की हत्या कर दी गई। कनाडा हत्याओं का देश बन गया है। वहां किसी दूसरे देश की तुलना में प्रति व्यक्ति ज्यादा आतंकी और गैंगस्टर मौजूद हैं। ये ड्रग तस्कर, आतंकवादी और गैंगस्टर आपस में लड़ रहे हैं। एक खुर्राट किस्म का खालिस्तानी, हेकड़ी दिखाते हुए सभी हिंदुओं को कनाडा छोड़कर जाने की चेतावनी देते हुए वहां मौजूद बड़े भारतीय समुदाय को धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। इस पर खामोश रहकर ट्रूडो एक और गलती कर रहे हैं। अब या तो वह मानसिक तौर पर अस्थिर हैं या वह खालिस्तानियों के साथ एक गंभीर किस्म के समझौते में हैं। उल्लेखनीय है कि ये वही खालिस्तानी हैं, जिन्होंने कई दशक पहले एक भारतीय विमान को उड़ा दिया था, जिसमें 300 से ज्यादा कनाडाई नागरिक मारे गए थे। तब उनके पिता कनाडा के प्रधानमंत्री थे। आज खालिस्तान समर्थक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ खालिस्तान समर्थक तो उनकी कैबिनेट में भी हैं। यह उनकी एक और गलती है। पांच साल पहले, जब ट्रूडो भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा पर खालिस्तानी के रूप में चिह्नित हो चुके लोगों को साथ लाए थे, तभी उन्होंने अपनी मनोदशा का परिचय दे दिया था। मुझे लगता है कि ट्रूडो के खालिस्तानी संरक्षकों ने उनसे नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के अंतिम घोषणापत्र में सभी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दों का उल्लेख करवाकर माहौल खराब करने के लिए कहा था। हालांकि वह ऐसा कर नहीं सके। हुआ यह कि जी-20 के नई दिल्ली घोषणापत्र ने, जिस पर ट्रूडो ने भी हस्ताक्षर किए थे, आतंकवाद की पूरी तरह से निंदा की। इस पर एक बिगड़ैल बच्चे की तरह प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित आधिकारिक जी-20 रात्रिभोज में भी शामिल होने से इन्कार कर दिया, जो एक मूर्खतापूर्ण फैसला था। उनका विमान खराब हो गया और उन्होंने होटल के अपने कमरे से बाहर आने से इन्कार करते हुए नई दिल्ली में दो दिन अतिरिक्त बिताए। यह उनका एक और मूर्खतापूर्ण कदम रहा। उनके खालिस्तानी आका उन्हें नौकरी से निकाल न दें, इसलिए वह भारत पर हास्यास्पद आक्षेप लगा रहे हैं। करीब एक दशक पहले जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा था, या हाल ही में जब अफगानिस्तान में शरण लिए जवाहिरी अमेरिकी ड्रोन मिसाइल का शिकार बना, तब क्रमशः पाकिस्तान व अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का क्या ट्रूडो ने विरोध किया? भारत की कड़ी प्रतिक्रिया और दूसरे देशों से समर्थन न मिलने पर अब ट्रूडो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि मामला शांत हो जाए।

महिला वोटरों की सियासी पिच

समीर चौगांवकर

संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार भोपाल पहुंचे जहां उन्होंने जंबूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। भोपाल के जंबूरी मैदान के 102 एकड़ क्षेत्र में टेंट लगाया गया था। भाजपा का दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ था जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। खास बात यह रही कि महिला आरक्षण विधेयक के पास होने की खुशी में भाजपा के महिला लोकप्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर जंबूरी मैदान में तीसरी बार कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करने पहुंचे मोदी ने प्रदेश में चल रही पांच यात्राओं का भी समापन किया। इस मौके पर मोदी ने मध्य प्रदेश की महिला वोटरों को याद दिलाया कि मोदी ने जो गारंटी दी थी, उसे 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाकर पूरा कर दिया है।

भोपाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर को जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करने पहुंचे। मोदी साढ़े चार साल बाद जयपुर पहुंचे हैं। इसके पहले मोदी 1 मई 2019 को जयपुर में सभा को संबोधित करने आए थे। आज जयपुर की दादिया पंचायत सांगानेर में मोदी की सभा हुई जहां मंच संचालन से लेकर पंडाल की सभी व्यवस्थाएं महिलाओं ने संभाला। मोदी के इन दोनों कार्यक्रमों की खास बात यह रही कि आयोजन के प्रमुख कार्यों की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने ही उठाया। शनिवार को वाराणसी में महिला आरक्षण विधेयक पर सियासी पिच तैयार करने की शुरूआत कर चुके मोदी भोपाल और राजस्थान में भी नारी शक्ति वंदन विधेयक पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाने के साथ ही महिलाओं के लिए उनकी सरकार के किए गए कामों का भी जिक्र किया। साफ है जो आरक्षण अभी दिया नहीं गया है उसका सिर्फ कानून बना है उसका लाभ लेने का काम मोदी और भाजपा दोनों ने शुरु कर दिया है। कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे जिसमें वो फसल बोने की कठिनाई उठाये बिना फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भारत में कुल मतदाता 91 करोड़ थे, जिसमें से 43.8 प्रतिशत महिला मतदाता और 47.2 प्रतिशत पुरूष मतदाता थे। वहीं 2022 में कुल मतदाता 95.1 करोड़ थे, जिसमें 46.1 प्रतिशत महिला मतदाता और 49 प्रतिशत पुरूष मतदाता थे। ध्यान देने योग्य यह है कि 2019 और 2022 के बीच महिला मतदाताओं में जहां 5.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं पुरूष मतदाताओं में 3.6 प्रतिशत की बढोतरी हुई। मोदी की नजर महिलाओं के वोट पर है जिसके दम पर मोदी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के चुनाव में कुल 66.8 प्रतिशत मतदान हुआ था और इसमें पुरूष और महिला की करीब करीब आधी भागीदारी थी। 2019 के चुनाव में भाजपा को कुल 37 फीसदी वोट मिले थे जिसमें लगभग 36 प्रतिशत वोट महिलाओं का था। इससे वह महिला मतदाता वर्ग की सबसे पसंदीदा पार्टी बनकर उभरी है। 2019 के आम चुनाव में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को सिर्फ 20 फीसदी महिलाओं ने वोट दिए थे।

लोकसभा चुनाव से लगभग 120 दिन पहले महिला आरक्षण कानून लाकर मोदी ने महिला मतदाताओं को रिझाने की कोशिशों में नया अध्याय जोड़ दिया है। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षाबंधन के दिन गैस सिलेण्डर की कीमतों में 200 रूपये कम कर दिए थे और 2016 में शुरू की गई उज्वला योजना को और 75 लाख घरों तक बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सरीखी दूसरी योजनाओं को भी यह कहकर प्रचारित करेगी कि इनसे महिलाओं को गरिमा, जीवनयापन में आसानी, वित्तीय शक्ति और समावेशन, आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं और यह सब मोदी के कारण संभव हो रहा है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से कई योजनाए ऐसी शुरू की जिसकी बड़ी लाभार्थी महिलाएं रही हैं। मोदी लगातार नारी शक्ति का जिक्र करते रहे और उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान की बात भी करते रहे। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरी बार भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, उस समय मोदी ने कहा था कि हमारी इस जीत की सारथी महिलाएं रहीं। जनवरी 2023 में दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने संबोधन में मोदी ने कहा था कि %महिला मोर्चा को अधिक से अधिक महिलाओं को भाजपा से जोड़ने के लिए काम करना चाहिए। इसके बाद केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की एक करोड़ लाभार्थी महिलाओ से संपर्क कर उनके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालने का कार्यक्रम महिला मोर्चा ने शुरू किया था।

भाजपा नेतृत्व ने महिला मोर्चा को टास्क देकर कहा था कि वह मोदी सरकार की योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं से मिलकर जाने कि कैसे मोदी की योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इसके लिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को 24 घंटे का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर मोदी सरकार की 12 योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। इसके साथ ही भाजपा ने फीडबैक का सिस्टम भी बनाया है, जिसके तहत जमीनी स्तर पर काम कर रही महिला कार्यकर्ता को लाभार्थी महिला से कोई फीडबैक मिले तो वह सीधे दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेज सकती है। संसद से महिला आरक्षण का विधेयक पारित करने के बाद अब अक्टूबर के अंत में भाजपा भोपाल और जयपुर में महिला लाभार्थी सम्मेलन करने वाली है जिसमें लाभार्थी महिलाओं से मोदी संपर्क और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भाजपा का महिला मोर्चा चुनाव वाले राज्यों के हर जिले से दस महिलाओं को सुषमा स्वराज सम्मान से सम्मानित करने का कार्यक्रम करेगी। यह अभियान लोकसभा चुनाव तक देश के सभी जिलों में पूरा करने की योजना है। महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के बाद अब भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सामाजिक समरसता और अन्न अभियान द्वारा कम से कम दो दलित महिलाओं को घर पर बुलाकर भोजन करवायेंगी। इसके अलावा भाजपा सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर, महिला प्रोफेशनल्स और महिला योग गुरू जैसे 50 क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं से संवाद कर पार्टी से जोड़ने का काम करेंगी। इसे स्मार्ट वूमन लीड़र फेस्टिवल नाम दिया गया है। महिला आरक्षण को भुनाने के लिए भाजपा 2024 में पहली बार मतदान करने वाली लड़कियों के लिए माय फर्स्ट वोट फार मोदी अभियान चलाएगी। इस अभियान की जिम्मेदारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और महिला मोर्चा की होगी। यह दोनों संगठन पहली बार मतदान करने वाली लड़कियों का वोटर कार्ड बनाने में मदद करने से लेकर मोदी को वोट क्यों देना चाहिए इस बारे में भी विस्तार से बताएगें।

भाजपा का यह भी आकलन है कि महिला आरक्षण विधेयक से उसे इसी साल महिला पहलवानों के उस विरोध प्रदर्शन से जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई होगी। एक कारण यह भी है कि भाजपा महंगाई सरीखे आर्थिक मुद्दों को लेकर चिंतित थी जिसका असर महिला मतदाताओं पर उनकी पकड़ पर पड़ रहा था। भाजपा का मानना है कि अगर पार्टी महिलाओं पर फोकस करते हुए दिखेगी तो महिला वोटरों में आई नाराजगी को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने जेंडर गैप कम करने के लिए बनाए गए जेंडर बजट में पिछले साल के मुकाबले 30 प्रतिशत का इजाफा किया है। इसके अलावा जिन योजनाओं में 100 प्रतिशत आवंटन महिलाओं के लिए है, उसके लिए 88 हजार करोड़ रू आवंटित किये गये है, जो पूर्व के मुकाबले 228 प्रतिशत ज्यादा है। यही कारण भी है कि राजस्थान में 1.3 करोड़ महिलाओं को स्मार्ट फोन, 3 साल डेटा फ्री और महिलाओं के लिए 1200 करोड़ का बजट रखा गया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना और उज्वला योजना के लिए 19,650 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। हालांकि एक ओर भाजपा महिला वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर उसकी दो बड़ी महिला नेता नाराज हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को शामिल करने की मांग पार्टी से की है, वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश से निकली चारों यात्राओं से दूरी बनाकर भाजपा को असहज कर दिया है। असंतुष्ट चल रही इन दो महिला नेत्रियों से मोदी कैसे निपटते हैं, यह देखना बाकी है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-2)

गतांक से आगे...

छठे अध्याय में समाधि के अभ्यास से परमेश्वरत्व की प्राप्ति, ज्ञानियों की उपासना पद्धति, अज्ञानियों की दु:खद स्थिति, मनोनाश का उपाय, वासना त्याग का उपाय, जीवन्मुक्त की महिमा, तृष्णा की त्याग विधि, चार प्रकार के निश्चय, अद्वैतनिष्ठ व्यक्ति के लिए संसार का अभाव, मुमुक्षु की ब्रह्मनिष्ठता और अन्त में इस उपनिषद् शास्त्र के पठन-पाठन का प्रतिफल वर्णित है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह महोपनिषद् अपने नाम के अनुसार अनेकानेक महत्त्वपूर्ण विषयों का बड़ी कुशलता के साथ विशद विवेचन प्रस्तुत करके अध्यात्मपथ के पथिकों का समुचित मार्गदर्शन करती है।

हे परमेश्वर मेरे समस्त अंग-अवयव वृद्धि को प्राप्त करें। वाणी, चक्षु कर्णेन्द्रिय आदि समस्त कर्मेन्द्रियाँ एवं ज्ञानेन्द्रियाँ, समस्त प्राण, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति ओजस-तेजस से परिपुष्ट एवं विकसित हों। मैं उपनिषद् में प्रतिपादित अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप को कभी भी अस्वीकार न करूँ तथा वह ब्रह्म भी हमारा कभी परित्याग न करे (वह मुझे सदैव अपने सामीप्य का बोध कराता रहे। (उस ब्रह्म के साथ मेरा तथा मेरे साथ उस ब्रा का प्रगाढ़ सम्बन्ध सतत बना रहे। उपनिषदों में वर्णित जो समस्त धर्म हैं, वे सभी उस परमात्म तत्त्व में निरत मुझमें सदैव प्रकाशित होते हुए स्थिर रहें। हे परमात्मन। त्रिविध ताप शान्त हों।

अब (ईश प्रार्थना के बाद) महोपनिषद् के व्याख्यान का शुभारम्भ किया जा रहा है। सृष्टि के आदि में एकमात्र भगवान् नारायण ही थे। इनके अतिरिक्त ब्रह्मा, रुद्र, आप: (जल), अग्नि एवं सोम आदि देवगण नहीं थे। ये लोक तथा पृथ्वीलोक भी नहीं थे और न ही नक्षत्र, चन्द्रमा एवं सूर्य आदि ही थे। ऐसी स्थिति में उन (विराट् पुरुष) को एकाकी रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।

उन (विराट् पुरुष) का अन्त:करण में स्थित ध्यान यज्ञस्तोम अर्थात् श्रेष्ठ यज्ञ कहलाया। उनके द्वारा एक कन्या एवं चौदह पुरुष प्रादुर्भूत हुए। जिनमें से चौदह पुरुष ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय सहित दस इन्द्रियाँ एकादश-तेजस्वी मन द्वादश अहंकार, तेरह और चौदह क्रमश: प्राण और आत्मा हैं तथा पन्द्रहवीं बुद्धि कन्या के नाम से कही गयी है। इनके अलावा पाँच सूक्ष्मभूत रूपी तन्मात्राएँ एवं पाँच महाभूत आदि इन पच्चीस तत्त्वों के संयोग से एक विराट् पुरुष के शरीर का निर्माण हुआ। उस (विराट् शरीर) में ही परमात्मरूप आदिपुरुष ने प्रवेश किया। इन पच्चीस तत्वों से संयुक्त पुरुष से) प्रधान संवत्सर आदि प्रकट नहीं होते (अपितु) आदि पुरुष के कालरूप संवत्सर से ही (संवत्सर) प्रादुर्भूत हुए हैं। तदनन्तर उन (विराट् पुरुष) भगवान् नारायण ने एक अन्य कामना से संकल्प युक्त हो अन्त:स्थ मन से ध्यान किया।

क्रमश: ...

अशोक सिंघल ने राममंदिर आंदोलन के माध्यम से जागरूकता पैदा की थी

मृत्युंजय दीक्षित

अशोक सिंघल का जन्म 27 सितंबर 1926 को आगरा में एक संपन्न उद्योगपति परिवार में हुआ। परिवार का वातावरण धार्मिक होने के कारण उनके मन में बचपन से ही हिंदू धर्म के प्रति प्रेम जागृत हो गया। राष्ट्रवादी विचारधारा के परिपालक व बहुसंख्य हिंदू समाज में राममंदिर आंदोलन के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने वाले विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अशोक सिंहल के अथक परिश्रम, समर्पित व्यक्तित्व व ओजस्वी उद्बोधनों का ही परिणाम है कि आज हिंदू समाज में सामाजिक समरसता का भाव दिखायी पड़ता है। संत समाज व विभिन्न अखाड़ा परिषदों को एक मंच पर लाने का अकल्पनीय कार्य भी अशोक ने ही संभव कर दिखाया। अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि मुक्ति के लिए जीवन अर्पण कर सतत प्रयासरत रहने वाले अशोक सिंघल जी ने हिंदुओं की खोती जा रही स्मृतियों को एक बार फिर से संजोने का काम भी कर दिखाया। यह उन्हीं के प्रयासों का परिणाम हैं कि आज देश का बहुसंख्यक समाज अपने आप को गर्व से हिंदू कहना चाहता है। हिंदुत्व के हित का संरक्षण करने व उसके दायित्व का वहन करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भी उन्हीं के प्रयासों से संभव हो सकी।

अशोक सिंघल जी ने देश, समाज, हिंदू सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति तथा अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण के लिए आंदोलनों की झड़ी लगा दी। वे सभी आयोजन काफी अनुशासित होते थे। जनसभाओं व कार्यक्रमों में अशोक जी के ओजस्वी भाषणों को सुनने के लिए भारी भीड़ जमा होती थी और जब यह भीड़ वापस घरों की ओर प्रस्थान करती थी तो उसमें एक नया पन व ताजगी की उमंग होती थी लेकिन किसी प्रकार की उत्तेजना या हिसक वातावरण का प्रदर्शन नहीं होता था। अशोक जी में विरोधाभासी विचार वाले विभिन्न समूहों को साथ में लेकर चलने की अभूतपूर्व कला थी।

संघ कार्य करते हुए अशोक सिंघल ने राष्ट्र के एक सच्चे साधक के रूप में अपने आपको विकसित किया और 1942 में संघ के स्वयंसेवक बने। संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी ने 1964 में जाने-माने संत महात्माओं के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। 1966 में विश्व हिंदू परिषद में अशोक जी का पदार्पण हुआ। अदभुत योजक शक्ति, संगठन कुशलता, निर्भीकता, अडिग व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की अशोक जी की विराटता ने हिंदू संगठन के रूप में विश्व हिंदू परिषद को पूरे विश्व में सबसे प्रखर हिन्दू संस्था के रूप में स्थापित किया। यह उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और विश्व के अन्य देशों में यदि कोई हिंदू विरोधी व भारत विरोधी घटना घटित होती है तो वह प्रकाश में आती है। अशोक जी जहां भारत में अपनी संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करने के लिए संघर्षरत रहे थे वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति किये जा रहे अत्याचारों के खिलाफ भी पूरे जोर शोर से आवाज उठाते थे। जम्मू-कश्मीर के हिंदुओं की समस्या के प्रति वे निरंतर गंभीर रहते तथा उनके दुखों को दूर करने का प्रयास भी करते थे । पांच शताब्दियों से चल रही श्री राम जन्मभूमि मुक्ति की लड़ाई 1984 में अशोक जी सहित महान संतों के नेतृत्व श्रीरामजन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के साथ पुन: प्रारंभ हुयी और 1990 में कारसेवकों का नृशंस हत्याकांड झेलते हुए हुए 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के विध्वंस और अस्थायी श्री राम लला मंदिर तक पहुँच गयी। यही श्री राम जन्मभूमि आन्दोलन का निर्णायक मोड़ और इस विषय पर हिन्दुओं की निर्णायक विजय सुनिश्चित करने का दिन था। यह उन्हीं का प्रयास रहा कि अदालत ने 30 सितम्बर 2010 को हाइकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक स्वर से उसी स्थान को श्रीरामजन्मभूमि माना।

नीति-निर्माता भी बनें महिलाएं

प्रभु चावला

संसद में पिछले सप्ताह एक इतिहास बना, जब 24 घंटे से भी कम समय में भारत के 63 साल पुराने संविधान में 128वें संशोधन को पास कर दिया गया। पिछले चार दशक से अधिक समय से, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण देने का वादा किया जाता रहा है, ताकि संख्या बल से उन्हें राजनीतिक अधिकार दिया जा सके। लेकिन अधिकार क्या बस संख्या से तय होता है? सत्ता समीकरण में महिलाओं की ताजा स्थिति से एक दुखद तस्वीर सामने आती है। जीवन के हर तबके में, राजनीति से लेकर कॉरपोरेट जगत तक में बढ़ती भागीदारी के बावजूद पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। बड़े फैसले पुरुष ही करते हैं। और लोकतंत्र के तीन स्तंभों- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका- में पुरुषों का दबदबा है।

महिलाओं को हाशिये पर रखने का यह रवैया 1947 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ। भारत के सभी 14 प्रधानमंत्रियों ने महिलाओं को सशक्त करने के बारे में उपदेश दिये, पर उनमें से किसी ने भी अपनी महिला सहकर्मियों को कोई अहम राजनीतिक या कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं सौंपी। हैरानी की बात है, कि उदार मत वाले जवाहरलाल नेहरू को भी पर्याप्त महिला मंत्री नहीं मिलीं। आजादी के बाद से कभी भी महिलाओं को कैबिनेट में 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा नहीं मिला। महिला केंद्रीय मंत्रियों की संख्या कभी भी आधे दर्जन से ज्यादा नहीं रही। यहां तक कि वाजपेयी जी की अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट में भी 34 मंत्रियों में महिला मंत्रियों की संख्या केवल दो थी। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट स्तरीय मंत्री थीं। मगर अपने दूसरे कार्यकाल में नेहरू ने किसी महिला को कैबिनेट में नहीं रखा और केवल लक्ष्मी मेनन को विदेश उपमंत्री बनाया।

लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने भी पर्याप्त महिला मंत्री नहीं बनाये। वर्ष 1962 से 1967 के बीच मंत्रिपरिषद में केवल पांच महिला मंत्री रहीं और उनको भी मामूली मंत्रालय दिये गये। इंदिरा गांधी ने 1967 में जब मामूली बहुमत से सत्ता में वापसी की, तो एक भी महिला को कैबिनेट में नहीं रखा। उनकी सरकार में एक महिला राज्य मंत्री थी और दो उपमंत्री। वर्ष 1972 में तीसरी बार दो तिहाई बहुमत से सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने तीन महिला उपमंत्री का फॉर्मूला जारी रखा। वर्ष 1977 में इंदिरा की हार के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। मोरारजी देसाई ने केवल चार महिलाओं को राज्यमंत्री बनाया और कोई बड़ा मंत्रालय नहीं सौंपा। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी 350 से ज्यादा सीटें जीत सत्ता में लौटीं, लेकिन पुरुष सहकर्मियों पर उनकी निर्भरता जारी रही और उन्होंने केवल तीन महिलाओं को राज्य मंत्री बनाया जिनमें शीला कौल शामिल थीं, जो उनकी संबंधी थीं। राजीव गांधी ने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की, जब अपने 401 सांसदों में से उन्होंने 12 महिलाओं को मंत्री बनाया। इनमें कोई भी कैबिनेट स्तर की मंत्री नहीं थी। शीला कौल को शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया।

वर्ष 1989 से 1991 के बीच सरकार में महिलाओं की स्थिति और कमजोर हुई। सामाजिक न्याय के मसीहा कहलाने वाले वीपी सिंह और चंद्रशेखर ने भी अपनी सरकारों में महिलाओं को बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया। वीपी सिंह ने एक महिला को राज्य मंत्री और एक को उपमंत्री बनाया। मगर यह संयोग से प्रधानमंत्री बननेवाले पीवी नरसिम्हा राव थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं को मंत्री बनाया। उनकी मंत्रिपरिषद में 12 महिला मंत्री थीं, और कैबिनेट में महिला को शामिल करनेवाले वह दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनकी 12 महिला सहकर्मियों में, शीला कौल कैबिनेट मंत्री बननेवाली देश की दूसरी महिला थीं, 40 सालों के बाद ऐसा मौका आया था। हालांकि, राव को भी नहीं लगा कि महिलाएं वित्त, रक्षा, गृह, मानव संसाधन, वाणिज्य या वित्त जैसे मंत्रालय संभाल सकती हैं। कांग्रेस की कठपुतली एचडी देवगौड़ा और आइके गुजराल की सरकारों को तो अपने मंत्री चुनने की आजादी ही नहीं थी।

वर्ष 1998 की वाजपेयी सरकार में कैबिनेट दर्जा प्राप्त एकमात्र महिला मंत्री सुषमा स्वराज थीं। उनके दूसरे कार्यकाल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गयी, जिनमें से तीन कैबिनेट मंत्री थे। मगर अच्छे मंत्रालय पुरुषों के ही पास रहे। महिला आरक्षण की हिमायती होने के बावजूद 2004 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार में केवल दो महिला कैबिनेट मंत्री बनायी गयीं, अंबिका सोनी और मीरा कुमार, जबकि आठ महिला राज्य मंत्रियों को मामूली मंत्रालय दिये गये। मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल में 15 महिलाओं को मंत्री बनाया और पांच को कैबिनेट प्रभार दिये। पर, किसी को भी अहम मंत्रालय नहीं दिये, सिवा ममता बनर्जी के, जो रेल मंत्री रहीं। बड़ा बदलाव 2014 में आया जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 10 महिला मंत्री बनाये और सुषमा स्वराज को पहली महिला विदेश मंत्री और निर्मला सीतारमण को वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार देकर इतिहास रचा। स्मृति ईरानी स्वतंत्रता के कैबिनेट स्तर की मानव संसाधन विकास मंत्री बननेवाली पहली महिला मंत्री बनीं। मोदी ने बाद में सीतारमण को रक्षा मंत्री, फिर वित्त मंत्री बनाया। मोदी के दूसरे कार्यकाल में, कैबिनेट स्तर की दो महिला मंत्री हैं, और महिला मंत्रियों की संख्या सात है। जहां तक राज्यों का प्रश्न है, तो 1947 के बाद से अब तक केवल 14 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं, जबकि पुरुष मुख्यमंत्रियों की संख्या 350 है।

हिन्द स्वराज

हिन्दुस्तान कैसे आजाद हो? (भाग-2)

गतांक से आगे...

प्रश्न- सभ्यता के बारे में आपके विचार मैं समझ गया। आपने जो कहा उस पर मुझे ध्यान देना होगा। तुरन्त सब कुछ मंजूर कर लिया जाय, ऐसा तो आप नहीं मानते होंगे, ऐसी आशा भी नहीं रखते होंगे। आपके ऐसे विचारों के अनुसार आप हिन्दुस्तान के आजाद होने का क्या उपाय बतायेंगे?

उत्तर- मेरे विचार सब लोग तुरन्त मान लें ऐसी आशा मैं नहीं रखता। मेरा फर्ज इतना ही है कि आपके जैसे जो लोग मेरे विचार जानना चाहते हैं, उनके सामने अपने विचार रख दूँ। वे विचार उन्हें पसंद आयेंगे या नहीं आयेंगे, यह तो समय बीतने पर ही मालूम होगा। हिन्दुस्तान की आजादी के उपायों का हम विचार कर चुके। फिर भी हमने दूसरे रूप में उनपर विचार किया। अब हम उन पर उनके स्वरूप में विचार करें। जिस कारण से रोगी बीमार हुआ हो वह कारण अगर दूर कर दिया जाय, तो रोगी अच्छा हो जायेगा यह जग मशहूर बात है। इसी तरह जिस कारण से हिन्दुस्तान गुलाम बना वह कारण अगर दूर कर दिया जाय, तो वह बंधन से मुक्त हो जायेगा।

प्रश्न- अंग्रेज हिन्दुस्तानी बनें, यह नामुमकिन है।

उत्तर- हमारा ऐसा कहना यह कहने के बराबर है कि अंग्रेज मनुष्य नहीं हैं। वे हमारे जैसे बनें या न बनें, इसकी हमें परवाह नहीं है। हम अपना घर साफ करें। फिर रहने लायक लोग ही उसमें रहेंगे; दूसरे अपने- आप चले जायेंगे। ऐसा अनुभव तो हर आदमी को हुआ होगा।

प्रश्न- ऐसा होने की बात तवारीख में तो हमने नहीं पढ़ी।

उत्तर- जो चीज तवारीख में नहीं देखी वह कभी नहीं होगी, ऐसा मानना मनुष्य की प्रतिष्ठा में अविश्वास करना है। जो बात हमारी अकल में आ सके, उसे आखिर हमें आजमाना तो चाहिए ही। हर देश की हालत एक सी नहीं होती। हिन्दुस्तान की हालत विचित्र है। हिन्दुस्तान का बल असाधारण है। इसलिए दूसरी तवारीखों से हमारा कम संबंध है। मैंने आपको बताया कि दूसरी सभ्यताएँ मिट्टी में मिल गयीं, जब कि हिन्दुस्तानी सभ्यताको आँच नहीं आयी है।

क्रमश: ...

यूपी में कांग्रेस को लड़ने से पहले खड़े होने की चुनौती

अनिल सिंह

उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस, सपा और रालोद मिलकर करेंगे या फिर अलग-अलग लड़ेंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है। सीट के बंटवारे को लेकर भी राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की कोशिश भले ही चल रही हो, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर गठबंधन में शामिल कई दलों की सियासत एक दूसरे के विरोध पर टिकी हुई है। तीन बैठकों के बाद भी गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन कोई मजबूत शक्ल ले पायेगा, और सीटों का बंटवारा आसानी से हो पायेगा, यह बड़ा सवाल है।

गठबंधन के सवालों के इतर कांग्रेस ने अजय राय को अध्यक्ष बनाकर उन अगड़ों को संदेश देने और जोड़ने की कोशिश की है, जो फिलहाल भाजपा खेमे में खुद को असहज पा रहा है। दरअसल, भाजपा दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिये पिछड़ों का जनाधार मजबूत करने में लगी हुई है। ओबीसी वर्ग के नेताओं को पार्टी के भीतर प्रमुखता दी जा रही है। कांग्रेस इसी को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। अगर भाजपा का जोर पिछड़ों पर है तो कांग्रेस का प्रयास अपने पुराने जिताऊ कॉम्बिनेशन ब्राह्मण, दलित और मुसलमान को अपने पाले में लाने का है।

भाजपा में दरकिनार किये जाने से नाराज सवर्ण वोटर भी विकल्प तलाश रहा है। घोसी उपचुनाव में सवर्ण मतदाता ने खुलकर सपा गठबंधन के पक्ष में अपना मत देकर संकेत भी दे दिया है कि वह भाजपा का बंधुआ नहीं है। जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान यह वर्ग भाजपा के साथ था। बहरहाल, इस स्थिति के बाद भी कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं है। सवर्ण वोटरों का भरोसा जीतना कांग्रेस के लिये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मुस्लिम तुष्टिकरण नीति सवर्णों के नजदीक आने की राह में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती रही है। यह स्थिति ध्रुवीकरण बढ़ाती है, जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है।

लेकिन भाजपा से लड़ने से पहले कांग्रेस के सामने यूपी में अपने संगठन को जमीन पर खड़ा करने की असल चुनौती है। सबसे ज्यादा सदस्यों वाली भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस को भी उसी स्तर की तैयारी की जरूरत है। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वह अपने बूते किसी

भी चुनाव में चमत्कार कर सके। कांग्रेस को प्रदेश के सभी बूथों पर कार्यकर्ता मिलना तक मुश्किल है। जाहिर है, जब तक कांग्रेस बूथ स्तर पर खुद को मजबूत नहीं करेगी, तब तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

उदाहरण के तौर पर देखें तो विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार सड़कों पर रही। कांग्रेस आंदोलनों के जरिए भाजपा सरकार को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश करती रही। सपा की बजाय कांग्रेस ही यूपी में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में दिखी। कांग्रेस महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी राज्य में घटित तमाम घटनाओं पर योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया। आंदोलन किया तथा राज्य के माहौल को गरमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आये तो कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब दौर में पहुंच गई।

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मात्र दो विधायक ही चुनाव जीत पाये। दोनों ही विधायक पार्टी की बजाय खुद की पकड़ की बदौलत विधानसभा पहुंचने में सफल हुए। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी सात फीसदी से सिमटकर तीन फीसदी पर पहुंच गया। दरअसल, कांग्रेस को यूपी में फिर से जिंदा करने के लिये केवल तेजतर्रार अध्यक्ष से काम नहीं बनने वाला है बल्कि इसके लिये जनता के एक बड़े वर्ग का भरोसा भी जीतना होगा, जो बहुत आसान नहीं है। अजय राय कांग्रेस के सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र बनारस तक ही सीमित है तथा उनकी जाति के वोटरों की संख्या भी पूरे प्रदेश में सियासी रूप से अप्रभावी है।

यह भी एक तथ्य है कि केवल आंदोलन से कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं किया जा सकता है। संगठन को भी गति देनी होगी। संगठन के स्तर पर अजय राय को काम करने का कोई विशेष अनुभव नहीं है, ना ही उनके सांगठनिक कौशल की कभी परीक्षा हुई है। बीते वर्ष उन्हें जोनल अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अपने जोन में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का प्रयास करते उन्हें नहीं देखा गया। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी यूपी में खासी सक्रिय रहीं, लेकिन विधानसभा में मिली करारी हार के बाद उन्होंने भी इस राज्य से मुंह मोड़ लिया है।

ऐसी स्थिति में कांग्रेस को खड़ा करना अजय राय के लिये बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। यूपी की सत्ता से कांग्रेस जब से बाहर हुई है, उसका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। वर्ष 2009 में कांग्रेस ने भले ही यूपी में 21 सीटें जीती हों, उसके बाद के चुनावों में वह क्रमशः दो एवं एक सीट पर सिमट गई। अजय राय के सामने एक और बड़ी चुनौती गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी है। कांग्रेस की मंशा 2009 को आधार मानकर सीटों का बंटवारा करने पर है, लेकिन सियासी जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव 2014 के आधार पर कांग्रेस को सीट देने की पेशकश कर सकते हैं।

गठबंधन की राह में सपा की महत्वाकांक्षा से निपटना भी कड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन से पहले सपा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन चाहती है। अतीत में सपा इन दोनों राज्यों में कुछ सीटें जीतती रही है। इस बार उसे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सपा सरकार का हिस्सा बन सकती है। सपा की कोशिश है कि कांग्रेस दोनों राज्यों में बड़ा दिल दिखाते हुए कुछ सीटें गठबंधन के तहत उसे भी दे ताकि वह भी सरकार बनने की स्थिति में सत्ता का हिस्सा बन सके। अब देखना है कि कांग्रेस इस पर क्या रवैया अपनाती है। उसके कदम पर ही यूपी में गठबंधन का भविष्य टिका हुआ है।

बिहार में अटकलों का बाजार गर्म, फिर से हो सकती है पलटी मार सियासत

एस पी सिन्हा

बिहार में क्या फिर से पलटी मार की सियासत होगी? क्या बिहार में फिर हवा का रुख बदल सकता है? यह सवाल बिहार की सियासत में लगातार चर्चाओं में है। हालांकि बिहार की सियासत को समझने वालों का मानना है कि नीतीश कुमार राजद के दबाव में हैं। उन पर तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जल्दी बनाने का दबाव है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से घिर चुके हैं। एक तरफ भाजपा लगातार उन पर हमला बोल रही है तो दूसरी ओर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक दबाव अलग से है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब नीतीश की हनक भी सत्ता में कमजोर पड़ती दिख रही है। ऐसे में सियासी चक्रव्यूह में फंसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार लालू यादव के आवास का चक्कर काट रहे हैं। वह भी बिना टाइम लिये या बात किये। आखिरकार नीतीश अचानक से लालू आवास क्यों पहुंच जा रहे हैं? जो राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा का विषय बन गया है। सवाल खड़ा होने लगा कि लालू जब पटना में नहीं थे तो साहब राबड़ी आवास क्या करने गए थे? इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या राबड़ी आवास कोई बड़ा फैसला लेने गए थे? दरअसल, राजद ने नीतीश को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी एकता का काम सौंपा। नीतीश ने इसे भी मनोयोग से किया भी और पटना में 15 विपक्षी दलों को जुटा कर अपना यह टास्क पूरा कर दिखाया। इसके लिए उन्हें पीएम पद की दावेदारी त्यागनी पड़ी। नीतीश ने यहां तक घोषणा कर दी कि साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस बीच नीतीश पर राजद का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे तेजस्वी यादव के लिए जितनी जल्दी हो, कुर्सी खाली कर दें। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच शह-मात का खेल चल रहा है। नीतीश के 16 सांसद अभी लोकसभा में हैं, जबकि राजद का कोई प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद हो सकते हैं। नीतीश ने इंडिया महागठबंधन बनाने में पूरा जोर लगा दिया था। वहीं उन्हें पीएम पद की उम्मीदवारी भी छोड़नी पड़ी तो संयोजक का पद भी हासिल नहीं हुआ। गठबंधन होने पर सीटों के बंटवारे की बात होनी है, लेकिन राजद और जदयू के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अब अगर सीट शेयरिंग होता है तो नीतीश के सबसे ज्यादा लोकसभा में प्रतिनिधित्व होने के कारण उनको हानि उठानी पड़ सकती है। कांग्रेस बिहार में 10 सीटों के लिए ताल ठोक रही है तो राजद चाहता है कि वो और जदयू समान सीट पर लड़े। नीतीश इस मुद्दे पर समझौता के पक्ष में नहीं हैं। वे अपनी सीट खोना नहीं चाहते हैं। जबकि लालू यादव पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर वे अपनी बात मनवाने की कोशिश शायद कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर प्रेशर बढ़ा दिया है। ऐसे में नीतीश के एनडीए में शामिल होने के कयास ने बिहार के राजनीतिक तापमान को और गर्म कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश के दबाव में आएंगे लालू? सियासी दाव पेंच खेले जाने लगे हैं। पंडित दीनदयाल की जयंती में जाना और पूर्व निर्धारित कैथल के महाजुटान में नहीं जाने से इन अटकलों को बल मिला है कि वह एक बार फिर पाला बदल सकते हैं।

मध्यप्रदेश में भाजपा ने दिग्गजों पर लगाया दांव

अंकित सिंह

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। हैरानी की बात यह है कि इसमें सात सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। इसमें तीन केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है, उनमें राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। ये सभी लोकसभा के सदस्य हैं। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर-1 से चुनाव लड़ेंगे। विजयवर्गीय को मैदान में उतारने के फैसले से 2018 में इंदौर-3 सीट से जीते उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय को फिर से पार्टी का टिकट दिए जाने की संभावना कम हो गई है क्योंकि भाजपा आम तौर पर चुनाव में एक ही परिवार के सदस्यों को अपना उम्मीदवार बनाने से बचती है। केंद्रीय मंत्री तोमर को दिमनी निर्वाचन क्षेत्र से, पटेल को नरसिंहपुर से और कुलस्ते को निवास सीट से मैदान में उतारा गया है। कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर, पार्टी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलने के बीच राज्य में सत्ता बरकरार रखने की अपनी कोशिश को रेखांकित किया है।

हालांकि बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के चुनावी लिस्ट को देख कर न सिर्फ राजनीतिक पंडित आश्चर्यचकित हुए बल्कि वह भी आश्चर्य में पड़ गए जिन्हें चुनावी मैदान में उतर गया है। इसके कई अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भाजपा के कुछ पदाधिकारियों का मानना है कि पार्टी के भीतर आंतरिक गुटबाजी चरम पर है जिसे खत्म करने की जरूरत है वरना 2018 के ही तरह पार्टी का इस बार भी हाल हो सकता है। भाजपा की दूसरी सूची कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। कांग्रेस लगातार एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। दूसरी सूची में भी भाजपा ने उन जगहों को प्राथमिकता दी है जिस पर पिछली दफा जीत नहीं मिली थी।

वहीं, दूसरी सूची में जो नाम सामने आए हैं उसमें पांच ऐसे हैं जो सिंधिया के बेहद करी भी माने जाते हैं। जिन लोगों को दूसरी सूची में रखा गया है वह सभी अपने-अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। उनका उस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। इन सबों को मैदान में उतर कर उस क्षेत्र के ज्यादातर सीटों पर भाजपा अपनी पकड़ को मजबूत करना चाह रही है। कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर, पार्टी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलने के बीच राज्य में सत्ता बरकरार रखने की अपनी कोशिश को रेखांकित किया है। इनमें से अधिकांश नेता अपनी लोकसभा सीट पर कई बार से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। दूसरी सूची के साथ, भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीट में से 78 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। पार्टी ने पिछले महीने 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 109 सीट मिली थी। हालांकि, कुछ विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई थी। मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नये कार्यकाल के साथ भाजपा सत्ता में लौटी थी।

भारत विरोधी शक्तियों को सह देना बंद करे कनाडा

विवेकानंद शाडिल

खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की मौत के मामले में इन दिनों भारत और कनाडा के बीच एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अपने देश की संसद में यह आरोप लगाया कि इस घटना में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ है और इसके बाद, कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इसके जवाबी प्रतिक्रिया में, भारत सरकार ने किसी भी संलग्नता से इंकार करते हुए, कनाडा के भी एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इसमें कोई दोराय नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो के शासनकाल में कनाडा खालिस्तानी चरमपंथियों के लिए एक बेहद सुरक्षित स्थान बन गया है, जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद ही चिंताजनक है। भारत में खालिस्तानी आंदोलन एक पृथक, संप्रभु सिख राज्य की लड़ाई है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यहाँ 'ऑपरेशन ब्लू स्टार', 'ऑपरेशन ब्लैक थंडर' जैसे कार्रवाइयों के बदौलत भारत सरकार ने इस आंदोलन को जड़ से मिटा दिया था। लेकिन, वास्तविकता यह है कि आज कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों इस आंदोलन के कई बड़े समर्थक हैं, जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को पलक देखते ही भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं।

भारत ने कई अवसरों पर कनाडा से खालिस्तानी आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की अपील की, लेकिन वह इसमें पूरी तरह से विफल रहा। यहाँ तक भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी कनाडाई प्रधानमंत्री से सिख विरोध प्रदर्शन के विषय में कड़ी चिंता जताई। लेकिन, इसका कोई लाभ नहीं हुआ। भारत और कनाडा के बीच, 1947 के बाद से ही बेहद अच्छे संबंध रहे हैं और दोनों देशों के बीच वर्तमान समय में द्विपक्षीय व्यापार प्रति वर्ष 6 बिलियन डॉलर

से भी अधिक है। अब जब, दोनों देशों के राजनयिक संबंध संकट में हैं, तो इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान और चीन जैसे आतंकी देश भी खूब उछल-कूद मचा रहे हैं। लेकिन, भारत को इसकी चिन्ता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वहीं, कनाडा और तमाम पश्चिमी देशों को यह समझना होगा कि आज भारत 1980 के दौर का कोई कमजोर और पिछलगुवा देश नहीं है। हम किसी भी स्थिति में अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उन्हें यह जता भी दिया है।

यदि हम हाल के वर्षों में भारत-कनाडा के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर गहन पड़ताल करें, तो पाएंगे कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल संभालने के बाद दोनों के रिश्ते ज़्यादा बेहतर कभी नहीं रहे। आज कनाडा विश्व में सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी में से एक की मेजबानी करता है। इस देश में भारतीय मूल के 16 लाख से भी अधिक लोग हैं, जो कनाडा के कुल आबादी का 3 प्रतिशत से भी अधिक है। ऐसे में, कनाडा के सरकार को किसी भी भारत विरोधी शक्ति के विरुद्ध तत्परता और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लेकिन, मामला ठीक इसके विपरीत है। हमारे विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत बीते कुछ वर्षों में कनाडा सरकार से 20-25 से अधिक लोगों के प्रत्यर्पण या कार्रवाई के लिए अनुरोध किया है। लेकिन, हमें उससे कोई भी मदद नहीं मिली है। अब जब कनाडा ने भारत पर एक बेहद ही निराधार और बेतुका आरोप लगाया है जो इससे खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों को लेकर जस्टिन ट्रूडो की निष्क्रियता को झलक ही रही है। इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि यह घटनाक्रम पूरी तरह से भारत की नई वैश्विक पहचान और सामर्थ्य को धूमिल करने और अपने राजनीतिक हित को साधने का एक प्रयास मात्र है। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर कई बार टिप्पणी की है, लेकिन अपने देश में खालिस्तान समर्थकों के प्रति उनकी उदासीनता ने लगातार उनके हौसलों को बढ़ाने का काम किया है। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पश्चिमी देशों की मीडिया की भरपूर आलोचना की और प्रधानमंत्री मोदी के अन्य विरोधी नेताओं से भी अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले पूरे मामले को ठीक से समझें। यह मामला व्यक्तिगत स्वार्थों से परे हमारे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और पहचान का है और इसमें हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। हमें यह पूरी तरह से ज्ञात है कि कनाडा में रहने वाले हमारे सिख भाइयों का मुट्ठी भर चरमपंथियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन, अगर कनाडाई सरकार ने चरमपंथियों की गतिविधियों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया तो इससे पूरे विश्व में फैले सिख समुदाय की बदनामी होती है। हम इसे भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो के शासनकाल में चरमपंथी समूहों ने बाहुबल और धन शक्ति का इस्तेमाल करके राजनीति में भी अपनी पहुँच बढ़ाई है। कनाडा की राजनीति के जाने-माने भारतीय विरोधी और खालिस्तानी हमदर्द सांसद जगमीत सिंह का नाम इसी का एक उदाहरण है।

राजनीतिक गठबन्धनों में उठापटक शुरू

अजय सेतिया

तमिलनाडु में जयललिता की अन्नाद्रमुक ने एक छोटी सी बात पर एनडीए से नाता तोड़ लिया है। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब के बाद तमिलनाडु चौथा राज्य है, जहां भाजपा के सहयोगी पार्टी से अलग हुए हैं। कर्नाटक में एचडी देवेगौडा की जेडीएस ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए एनडीए से नाता जोड़ लिया है। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी के दो टुकड़े हो चुके हैं। चौटाले के बड़े बेटे अजय चौटाला ने भारतीय राष्ट्रीय लोक दल बना ली थी, उनके बेटे दुष्यंत चौटाला हरियाणा की भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने एलान कर दिया है कि वह एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओम प्रकाश चौटाला के दूसरे बेटे अभय चौटाला की आईएनएलडी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब वह इंडी एलायंस में जाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना टूट कर आधी एनडीए में चली गईं, आधी इंडी एलायंस में। बिहार में जेडीयू भी टूटने के कगार पर है। अमित शाह बाकायदा बिहार में एलान करके आए हैं।

कर्नाटक में जेडीएस का मुख्य आधार एचडी देवेगौडा की अपनी जाति वोक्कालिगा और मुस्लिम रहे हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में मुसलमानों के जेडीएस से नाता तोड़कर कांग्रेस के साथ जाने के बाद देवेगौडा के लिए जेडीएस का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया था। विधानसभा चुनावों में जेडीएस को सिर्फ 13.27 प्रतिशत वोट और 19 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने देवेगौडा के वोक्कालिगा वोटरों में भी अच्छी खासी सेंधमारी की थी। एक तरह से कांग्रेस ने जेडीएस को निगल लिया था। देवेगौडा को भारतीय जनता पार्टी ने जून में एनडीए में शामिल होने की पेशकश की थी। देवेगौडा तो तभी पूरी तरह तैयार थे, लेकिन उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने फैसला करने में चार महीने लगाए। उन्हें फैसला लेने में इसलिए देर लगी, क्योंकि उन्हें जेडीएस के मुस्लिम वोटबैंक को लेकर भ्रम था। कुमारस्वामी जब आश्वस्त हो गए कि मुस्लिम वोट वापस नहीं आएगा और वोक्कालिगा वोटरों को बचाना जरूरी है, तो उन्होंने सोच समझ कर भाजपा के साथ जाने का फैसला किया।

कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा के लिए भी कर्नाटक की 25 लोकसभा सीटें बचाना अति महत्वपूर्ण हो गया है। वह जेडीएस से गठबंधन के बिना ये सीटें नहीं बचा सकती। लोकसभा चुनाव में जेडीएस को 9.67 प्रतिशत वोट मिले थे। उधर जेडीएस के लिए भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए लोकसभा सीटें जीतना जरूरी है। देवेगौड़ा की पार्टी कर्नाटक की मांड्या, हासन, बेंगलुरु (ग्रामीण) और चिकबल्लापुर सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, भाजपा ये चारों सीटें देने को तैयार हो गई थी। 2019 में जेडीएस सिर्फ हासन सीट पर जीत पाई थी। जबकि मांड्या, बेंगलुरु (ग्रामीण) और चिकबल्लापुर सीटों पर भाजपा जीती थी। हासन से पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने चुनाव जीता था, लेकिन पहली सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी सांसदी भी रद्द कर दी थी।

देवेगौडा को पता था कि जेडीएस के साथ जो मुस्लिम नेता बचे हैं, वे भी भाजपा के साथ जाने पर

उनका साथ छोड़ देंगे। वही हुआ भी। गठबंधन का एलान होते ही कर्नाटक में जेडीएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैयद शैफुल्ला ने पार्टी छोड़ने का एलान कर दिया। देवदुर्गा से पार्टी विधायक करीअम्मा नायक ने भी गठबंधन के खिलाफ आवाज उठाई है। केरल में पार्टी के दोनों विधायकों ने अल्टीमेटम दिया है कि या तो जेडीएस अपना फैसला बदले या फिर वो एनडीए या बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। इन दो विधायकों में से एक राज्य सरकार में इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर के. कृष्णकुट्टी का कहना है कि भले ही पार्टी ने एनडीए का दामन थामा हो लेकिन केरल में जेडीएस पहले की तरह वामपंथियों के साथ गठबंधन जारी रखेगी। वहीं दूसरे विधायक मैथ्यू टी थॉमस जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वह भी एनडीए में जाने के खिलाफ हैं। अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्टी की राज्य इकाई की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। केरल का जनता दल शुरू से ही भाजपा विरोधी लाईन अपना कर चलता रहा है। जब जनता दल और समता पार्टी से जेडीयू बनी थी, जो एनडीए का हिस्सा बनी थी, तब भी केरल के जनता दल ने शरद यादव से बगावत करके खुद को अलग कर लिया था, और बाद में केरल यूनिट को जेडीएस का हिस्सा बना लिया था।

तमिलनाडु में तो भाजपा और अन्नाद्रमुक में लंबे अरसे से तनाव चल रहा था। इसकी वजह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई को माना जाता है, क्योंकि वह जब से अध्यक्ष बने हैं, अन्नाद्रमुक से गठबंधन तोड़ने की वकालत करते रहे हैं। वह लगातार अन्नाद्रमुक महासचिव पलानीस्वामी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। हालांकि इस तनाव के दौरान ही अन्नाद्रमुक के महासचिव पलानीस्वामी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाक़ात करके गठबंधन को पक्का कर दिया था। लेकिन सनातन के मुद्दे पर द्रविड़ बनाम सनातन का विभाजन शुरू हुआ तो अन्नामलाई ने अपनी मुहिम फिर तेज कर दी। अन्नामलाई ने द्रमुक मूवमेंट के नेता और अन्नाद्रमुक के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन के गुरु अन्नादुरई के बारे में टिप्पणी की कि उन्होंने 1950 में हिन्दू धर्म के खिलाफ बोला था, लेकिन जब उनका विरोध हुआ तो उन्होंने माफी मांग ली थी। हालांकि तमिलनाडु के अखबारों में उनके इस बयान का खंडन हुआ कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी।

इसके अलावा अन्नामलाई ने जयललिता के भ्रष्टाचार को लेकर भी बयानबाजी की। जिससे अन्नाद्रमुक के नेता उनसे काफी खफा थे। भाजपा के साथ गठबंधन के बारे में फैसला लेने के लिए सोमवार को अन्नाद्रमुक ने पार्टी की बैठक बुलाई, जिसमें भाजपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया गया। 18 सितंबर को अन्नाद्रमुक नेता डी जयकुमार ने गठबंधन तोड़ने का संकेत देते हुए कहा था कि तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख अन्नामलाई हमारी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों सीएन अन्नादुरई और जयललिता पर बयानबाजी करते हैं। हमारे कार्यकर्ता इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों दलों में कडवाहट की एक वजह यह भी थी कि मार्च में भाजपा के पांच नेता अन्नाद्रमुक में शामिल हो गए थे। इनमें पार्टी के प्रदेश आईटी विंग के प्रमुख सीआरटी निर्मल कुमार भी शामिल हैं। निर्मल के अलावा 13 और नेता भी अन्नाद्रमुक में चले गए। इससे पहले अन्नाद्रमुक के बड़े नेता और पूर्व मंत्री नैनार नागेंद्रन पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और अभी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। तमिलनाडु विधानसभा में भाजपा के चार एमएलए हैं।

प्रकृति की शक्ति कहलाते हैं भगवान गणेश

32 रूप जानें इनके नाम और महत्व

देशभर में धूमधाम के साथ गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, बता दें कि गणेश चतुर्थी से शुरू होकर पूरे 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जाता है।

भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता, मंगलकारी, बुद्धिदाता और विग्घहर्ता कहलाते हैं। भगवान गणेश को हम बप्पा, गणेशा, गणपति, एकदंत, लंबोदर आदि जैसे कई नामों से जानते हैं। अनेक नामों के साथ ही भगवान के कई रूप भी हैं। मुग्दल और गणेश पुराण में भगवान गणेश के 32 मंगलकारी रूपों का वर्णन मिलता है।

बता दें कि, कर्नाटक में मैसूर के पास नंजनगुड शिव मंदिर में गणेश जी के 32 रूप मौजूद हैं। भगवान गणेश के इन रूपों की अपनी विशेषता है और इनसे महत्व-पूर्ण प्रेरणा भी मिलती है। जानते हैं गणेश जी के इन 32 रूपों के नाम और इसके महत्व के बारे में।

श्री बाल गणपति: यह गणेशजी का बाल रूप है, जिसे धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का व भूमि की उर्वरता का प्रतीक माना गया है। इस रूप में भगवान के चार हाथ हैं और चारों हाथों में आम, केला, गन्ना और कटहल फल है।

तरुण गणपति: भगवान गणेश का यह रूप युवावस्था की ऊर्जा का प्रतीक है। इसमें भगवान की प्रतिमा किशोर रूप में है और उनका शरीर लाल रंग में चमकता हुआ है। इसमें भगवान की 8 भुजाएं हैं। सभी भुजाओं में फल, मोदक और अस्त्र-शस्त्र हैं।

भक्त गणपति। भगवान गणेश का यह रूप पूर्णिमा की चांद की तरह चमकीला और श्वेतवर्ण है। इस रूप में भगवान के चार हाथ हैं, जिनमें फूल-फल हैं।

वीर गणपति: नाम की तरह यह गणेशजी का योद्धा रूप है, जिसमें भगवान के 16 हाथ हैं। अपने हाथों में भगवान गदा, चक्र, तलवार, अंकुश जैसे कई अस्त्र लिए हुए हैं। इस रूप में भगवान गणेश युद्ध कला को दर्शाते हैं और विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।

शक्ति गणपति: इस रूप में भगवान भक्तों को शक्तिशाली बनने का आशीष देते हैं। इस रूप में भगवान अभय मुद्रा में हैं और उनके चार हाथों में अस्त्र-शस्त्र और माला हैं।

द्विज गणपति: भगवान का यह रूप ज्ञान और संपत्ति के गुण को दर्शाता है। इसमें भगवान के दो मुख और

चार हाथ हैं, जिसमें वे कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र लिए हुए हैं।

सिद्धि गणपति: गणेशजी का यह रूप पीतवर्ण है और यह रूप बुद्धि और सफलता के प्रतीक माना जाता है। इसमं भगवान के चार हाथ हैं और वे आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। भगवान के सूंड में मोदक भी है।

उच्छिष्ट गणपति: गणेश इस रूप में नीलवर्ण है और धान्य के देवता हैं, जो मोक्ष और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। भगवान अपने हाथ में वाद्य यंत्र भी लिए हुए हैं।

विघ्न गणपति: गणेशजी का यह रूप स्वर्ण रंग की तरह है और उनके आठ हाथ हैं। इस रूप में भगवान गणेश विष्णु जी की तरह दिखाई देते हैं। क्योंकि वे अपने हाथों में शंख और चक्र लिए हुए और आभूषण धारण किए हुए रूप में हैं।

क्षिप्र गणपति: भगवान गणेश का यह रूप रक्तवर्ण हैं। मान्यता है कि, इस रूप में भगवान की पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान के चार हाथ हैं। एक हाथ में कल्पवृक्ष की शाखा लिए हुए हैं और अपनी सूंड में वे रत्नों से भरा कलश लिए हुए हैं।

हेरम्ब गणपति: इस रूप में भगवान के पांच सिर हैं। भगवान के इस विलक्षण हेरम्ब रूप को दुर्बलों का रक्षक कहा जाता है। इस रूप में भगवान की सवारी मूषक नहीं बल्कि शेर है और उनके दस हाथ भी हैं, जिसमें भगवान फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं।

लक्ष्मी गणपति: भगवान गणेश के इस रूप में बुद्धि और सिद्धि भी साथ है। भगवान अभय मुद्रा में हैं। उनके आठ हाथों में एक हाथ में तोता है।

महागणपति : इस रूप में शिवजी की तरह भगवान गणेश के तीन नेत्र हैं। साथ ही दस हाथ भी है जो दसों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में भगवान का एक मंदिर द्वारका में भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यहां श्रीकृष्ण ने भी गणेशजी की पूजा की थी।

विजय गणपति: गणेश जी इस रूप में बड़े आकार के मूषक पर सवार हैं। मान्यता है कि, इस रूप में भगवान की पूजा करने के तुरंत कष्टों से राहत मिलती है।

नृत्य गणपति: इस रूप में भगवान गणेश प्रसन्न होकर एक कल्पवृक्ष के नीचे नृत्य करते हए हैं। ललित कलाओं मे सफलता के लिए इस रूप में भगवान की पूजा करना लाभकारी माना जाता है।

उर्ध्व गणपति: इस रूप में भगवान के साथ शक्ति भी हैं, जो उनके गोद में विराजित हैं और भगवान ने उन्हें अपने बाएं हाथ से थाम रखा है। भगवान के आठ हैं। एक हाथ में गणपति अपना टूटा हुआ दांत लिए हुए हैं, बाकी हाथों में कमल फूल और प्राकृतिक सम्पदाएं हैं।

एकाक्षर गणपति: भगवान गणेश का यह रूप पिता शिव के समान है। गणेश जी के तीन नेत्र हैं और मस्तक पर चंद्रमा विराजित है। माना जाता है कि, इस रूप भगवान की पूजा करने से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में करने में मदद मिलती है।

वर गणपति: भगवान गणेश का यह रूप वरदान देने के वाला माना जाता है। इस रूप में वे अपनी सूंड में रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में भगवान के साथ एक देवी भी विराजित हैं, जिसके हाथ में विजय पताका है।

त्र्यक्षर गणपति: भगवान गणेश का यह ङ्कओमफरूप है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी हैं। इस रूप में भगवान की पूजा करने से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है।

क्षिप्रप्रसाद गणपति: भगवान का यह रूप शांति और समृद्धि प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इस रूप में भगवान घास से बने सिंहासन पर बैठे हुए हैं।

हरिद्रा गणपति: भगवान गणेश का यह रूप हल्दी से निर्मित है और वे राजसिंहासन पर बैठे हुए हैं। मान्यता है कि इच्छा पूर्ति के लिए इस रूर में भगवान की पूजा करना फलदायी होता है।

एकदंत गणपति: इस रूप में भगवान गणेश का पेट अधिक बड़ा दर्शाया गया है। मान्यता है कि इस रूप में भगवान अपने भीतर ब्रह्मांड समाए हुए हैं।

सृष्टि गणपति: गणेश भगवान का यह रूप ब्रह्मा के समान है और प्रकृति की कई शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उद्दंड गणपति: भगवान का यह रूप उग्र है। उनके 12 हाथ हैं और साथ ही देवी शक्ति भी विराजित हैं। यह रूप सांसारिक मोह-माया के बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा देता है।

ऋणमोचन गणपति: गणेश जी इस रूप में भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। उनके चार हाथ और श्वेतवर्ण हैं। इस रूप में भगनवान जिम्मेदारियों का वहन करने की प्रेरणा देते हैं।

ढुण्ढि गणपति: गणेश जी इस रूप में रक्तवर्ण है और उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। इस रूप में गणेश पिता शिव के संस्कारों यानी रुद्राक्ष को लिए विराजित हैं।

द्विमुख गणपति: भगवान गणेश के इस रूप में उनके दो मुख है और चार हाथ हैं। दोनों मुखों में सूंड ऊपर उठी हुई हैं। उनके शरीर का रंग नीले और हरा है।

त्रिमुख गणपति: नाम की तरह इस रूप में गणेश जी के तीन मुख हैं और छह हाथ भी हैं। एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। दाएं और बाएं तरफ के मुख की सूंड ऊपर उठी है और भगवान स्वर्ण कमल पर विराजित हैं।

सिंह गणपति: भगवान गणेश इसमें शेर के रूप में दर्शाएं गए हैं। उनका मुख शेर की तरह है और सूंड भी है। उनके आठ हाथ हैं, जिसमें एक हाथ वरद मुद्रा में है और दूसरा अभय मुद्रा में।

योग गणपति: भगवान गणेश इस रूप में एक योगी के समान हैं। वे मंत्रों जाप कर रहे हैं और पैर योगिक मुद्रा में है।

दुर्गा गणपति: भगवान गणेश का यह अजेय रूप विजय मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं और लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जोकि ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान के हाथ में धनुष भी है।

संकष्टहरण गणपति: भगवान गणेश का यह रूप भय और दुख को दूर करने की प्रेरणा देता है। गणपति के साथ उनकी शक्ति भी विराजित हैं, जिसे उन्होंने एक हाथ से थामा है और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। देवी शक्ति के हाथ में कमल पुष्प है।

ये पहला ऐसा मंदिर जहाँ बच्चों के जात जडूला लगाने पर चुप रहती है मां

गूंगी माई जो सबको बोलना सिखाती हैं

हमारे देश में अनेकोनेक मंदिर है जहाँ आस्था और विश्वास का अद्भुत मिलाप देखने को मिलता है। राजस्थान के झुंझुनू जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित देई माता (गूंगी माई) का मंदिर स्थापित है जहाँ मां महामाया अपने दिव्य रुप में विराजमान है। भारत में संभवतः ये पहला ऐसा मंदिर जहाँ बच्चों के जात जडूला लगाने पर मां चुप रहती है। मंदिर परिसर में पहुंचते ही मां चुप हो जाती है और मन ही मन मां की प्रार्थना करती है। खासकर जिस बच्चे का जड़ूला उतारा जाता है, उसकी मां मंदिर परिसर में बोलती नहीं। इसके पीछे मान्यता है कि बोलने पर माता जात स्वीकार नहीं करती।

इसके पीछे मान्यता है झुंझुनू जिले की सिंघाना पंचायत समिति के मोई भारू पंचायत में स्थित देई माई (गूंगी माई) माता मंदिर कुठानिया धाम में वर्षों से यह परम्परा चली आ रही है। यहां छोटे बच्चे की जात लगाई जाती है. कहा जाता है कि जब तक बच्चे की जात नहीं लगाई जाती तब तक बच्चा बोलने नहीं लगता है। उसके बोलने व अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता को धोक लगाने व जात जडूले उतारने वालों की भीड़ लगी रहती है।

लोकमान्यता है कि देई माई और उनकी छ बहनें थी एक भाई जिनका नाम क्षेत्रपाल था। देई माई, गूंगी माई तो तातीजा (कुठानिया गाँव) में, महराणा, माखर,सामोद व अन्य स्थानों पर विराजमान हो गई

यहां पर गूंगी माई का मंदिर भी है। इन्हें विशेष तौर पर गूंगे, बहरों, अपंगों, अन्धों, कोढ़ियों व मानसिक विक्षिप्तों को ठीक करने के लिए पूजा जाता है। माना जाता है कि सभी अंग प्रत्यंगों का गर्भ में ही विकास करने वाली (अंग देने वाली) माता श्री देई माई को सही से नहीं पूजा जाने पर ही ये सब विकृतियों मानव शरीर में होती हैं। जो गूंगी माई के आर्शीवाद से ही ठीक हो पाती हैं। इसीलिए इस मंदिर में पहले देई माई की पूजा होती है और उसके बाद गूंगी माई की।प्रदेश में इसके अलावा गूंगी माई का कहीं भी मंदिर नहीं है।

प्राचीन मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मां दुर्गा ने जब कन्या रूप में भंडारा किया था तब भैरवनाथ ने भंडारे को अपवित्र करने के लिए मांस और मदिरा की मांग की थी। माता के मना करने पर उसने माता को ललकारा, तब माता ने छेत्रपाल के संरक्षण में 9 माह तक मौन रहकर भैरव का संहार करने के लिए सिद्धियां अर्जित की। इन 9 महीने में माता ने मौन रहकर ही जनता के दुख दूर किए। तभी से इनकी गूंगी माता के रूप में पूजा की जा रही है।

कहा जाता है कि इसके अलावा 1594 में अकबर ने मैया के विशाल मंदिर को तुड़वा दिया था।तब मंदिर तोड़ने वाले सिपाही और उनके बाल बच्चे गूंगे बहरे हो गए थे। जब यह बात अकबर को पता चली तो उसने और उसके सिपाहियो ने मंदिर में आकर माफी मांगी और मैया की जोत जलाई। तब सभी की आवाज वापस आ गई थी। तब से मुस्लिम समाज की औरतें भी मैया के दरबार में अपने बच्चों को धोक लगवाती हैं।

श्री देई माई (गूंगी माई) माता को जगदम्बा मातेश्वरी

देई माई (गूंगी माई) राजस्थान ही नहीं पूरे भारत वर्ष ये संभवतः पहला मंदिर होगा, जहाँ मां चुप रह करके अपने बच्चें को बोलने की प्रार्थना करती है।

का ही रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कर माता सती के शव के टुकड़े किए थे तब जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इन्ही शक्तिपीठों में पहले स्थान पर हिंगलाज शक्तिपीठ है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। बताया जाता है कि यहां सती माता का मस्तक गिरा था।स्थानीय मुस्लिम भी हिंगलाज माता में आस्था रखते हैं और मन्दिर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मुस्लिम हिंगलाज माता मंदिर को नानी का मंदिरङ्घ कहते हैं। इसके अलावा जैसलमेर में आवड़ माता के नाम से भी इनका मंदिर है।

श्री देई माई, गुंगी माई का मन्दिर कब आस्तित्व में आया इसका कोई वास्तविक ठोस प्रमाण कहीं नही मिलता। इसके लिए दंत कथाओं के आधार पर सिर्फ यहीं तर्क दिया जाता रहा है कि जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज नें श्री देई माई, गुंगी माई व क्षेतरपाल जी महाराज को कुठानियां धाम में विराजमान किया तब भादरियाराय माता के अनन्य भक्त श्री रघुवीर सिंह जी के भंवर पुत्र श्री चतर सिंह भाटी जो उस समय खेतडी महाराज के सेनापति थे, को सपनें में मैया ने दर्शन दिये और कुठानियां धाम आकर जोत जगानें को कहा। कहा जाता है कि श्री चतर सिंह जी नें तभी आजीवन पूजा का कयप्रण लिया और माता के बतायें अनुसार जगह कुठानिया धाम आकर स्नान कर, खाली पेट, बिना बोले मैया की पुजा अर्चना की व नित करते रहे।उसके बाद बताया जाता है कि श्री चतर सिंह जी के छोटे भाई श्री त्रिलोक सिंह अपनें भाई से मिलनें जैसलमेर से ऊंट पर खेतडी जा रहे थे, जब वे कुठानियां धाम के नजदीक पहुंचे तो पिछे से नंगली सलेदी सिंह के डाकुओं ने उन्हें घेर लिया व ऊंट व जो कुछ उनके पास था वो देनें की बात कही। इस पर श्री त्रिलोक सिंह नें मैया का आवाहन कर अपनी तलवार निकालकर उनका सामना करनें लगे। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद भी जब श्री त्रिलोक सिंह जी नें उन्हें न अपनां उंट दिया ना किसी को अपनें हाथ ही लगानें दिया, तो थककर डाकुओं नें उनसें सुलह करनें की बात कहीं। सुलह में श्री त्रिलोक सिंह भाटी को डाकुओं नें अपना मुखिया बना लिया, और यह तय किया गया की अमीरों से धन लूटकर इस इलाके के गरीब लोगों की सहायता की जावेगी और शेष प्राप्त धन से श्री देई मैया का मन्दिर बनाया जायेगा। कुछ समय बाद जब यह बात सेनापति श्री चतर सिंह जी को पता लगी तो उन्होनें श्री त्रिलोक सिंह जी को श्री देई माई मन्दिर में पूजा करके बाहर निकलते ही हीरासत में ले लिया व सगा भाई होनें पर भी खेतडी महाराज के समक्ष बंदी बना कर पेश कर दिया। खेतडी महाराज की रानी जैसलमेर के भाटी राजपुतों की बेटी थी। कहा जाता है कि रानी को मैया द्वारा यह दर्शाव दिया गया कि तुम्हारा भाई अपने सगे भाई द्वारा बंदी बना लिया गया है। तब रानी नें पूरा दर्शाव वाला वर्तान्त महाराज को बताया तो महाराज ने श्री चतर सिंह जी को बुलवाया व सब वर्तान्त पूछकर श्री त्रिलोक सिंह को बंदीग्रह से बाहर निकलवा लिया। उसी समय गांव कुठानियां के कुछ लोग राजदरबार पहुंचे और उन्होनें महाराज को बताया की किस तरह उनका क्षेत्र नंगली सलेदी सिंह के डाकुओं से भयभीत है। उन्होनें महाराज से श्री त्रिलोक सिंह को कुठानियां भेजनें व वही रहनें के लिए अर्जी लगाई।

गूंगी माई की जात जडुला भादवा सुदी सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलते हैं। मां का दरबार वैसे तो पूरे वर्ष अपने निर्धारित समय पर खुलता पर इस विशेष अवसर पर मंदिर से एक विशेष संकेत दिया जाता है जिसे डंका बोलते है उसके बाद जात जडूले का क्रम शुरू होता है।

गूंगी माई को माने ने वाले श्रद्धालु पूरे भारत में बैसे है।

महाराज नें श्री त्रिलोक सिंह को सिंघानां के तहसीलदार पद पर नियुक्त किया व कुठानियां रहकर गांव वालों की रक्षा करनें और मन्दिर निर्माण के कार्य को पूरा करनें को कहा। उस समय बना मन्दिर काफी बडा था व उसमें रखी मैया की मूर्ति भी काफी बडी थी, इसका अनुमान सन 2003 में महन्त श्री सुमेर सिंह जी द्वारा छेतरपाल जी महाराज के देवरे को दुरस्त करवानें के लिए करवाई गई खुदाई में मिलें सुदर्शन चक्र को देखकर लगाया जा सकता है। मैया के मन्दिर को व मूर्तियों को मुगल काल में तोड दिया गया था।

जिसका प्रमाण श्री छेतरपाल जी महाराज की मुर्ति को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें अभी भी चोटों के निषान ज्यों के त्यों मोजूद हैं।

उसके बाद श्री त्रिलोक सिंह जी के पुत्र श्री प्रताप सिंह जी व श्री हाथी सिंह जी खेतडी महाराज की सेना के सेनापति थे। श्री प्रताप सिंह जी को श्री देई माई द्वारा यह दर्नश दिया गया की अमुक जगह राजा द्वारा स्थापित उसी जगह महामाई का मंदिर निर्माण किया जावेगा और उस समय झाडियों में छुपा शेर राजा पर हमला करेगा। श्री प्रताप सिंह जी नें यह बात अपनें भाई हाथी सिंह जी को बताई और महाराज के साथ शिकार पर जाते समय श्री प्रताप सिंह जी व श्री हाथी सिंह जी महाराज के बिलकुल पिछे पिछे थे, वो जैसे ही शेर के हमले वाले स्थान पर पहुंचे तो एकदम सर्तक हो गये और जैसे ही शेर नें झाडियों से निकलकर हाथी पर बैठे राजा पर हमला किया तो बताया जाता है कि श्री प्रताप सिंह जी द्वारा घोडे पर बैठे बैठे ही एक ही वार में षेर के दो टुकडे कर दिये। महाराज नें खुश होकर श्री प्रताप सिंह भाटी को 1000 वीघा का बाड (जमीन) दिया, जिसमें अभी कुठानियां की सीमा से लगे अन्य गांव बसे हुए है, जो बाद में श्री प्रताप सिंह जी द्वारा गरीबों में बांट दिया गया। श्री चतर सिंह जी के समय से ही श्री देई माई की सेवा पूजा भाटी परीवार द्वारा की जा रही हैं, उस समय से मैया के चमत्कारों की कीर्ति काफी दूर दूर तक है।

मैया के दरबार में आनें वाला चढावा मन्दिर निर्माण व अन्य धार्मिक कार्यों में लगता था, जिसका लेखा जोखा खेतडी रियासत में रखा जाता था। रियासतों के विलिनीकरण के बाद मन्दिर का चढावा खेतडी राजघरानें के वंशजों द्वारा बनाये गये ट्रस्ट मफ शार्दुल एजुकेषनल ट्रस्ट मफ झुन्झुनूं में जानें लगा। श्री प्रताप सिंह जी के वंशज श्री हरी सिंह जी नें भी आजीवन शादि नहीं करनें व मैया की सेवा पूजा करते रहनें का प्रण किया था। वो मन्दिर के पास ही कुटिया बनाकर रहते थे। उन्होनें ही लोगों से चंदा ईक्ठा कर मन्दिर के पास ही जोहड (तालाब) खुदवाया। जो बाद में आस्था का केन्द्र बना।

श्री हरी सिंह जी भाटी द्वारा वर्तमान प्रन्यास अध्यक्ष महन्त श्री सुमेर सिंह जी को गोद लिया गया। महन्त श्री सुमेर सिंह जी अपनें दादा के साथ बचपन से मैया की सेवा पूजा में ध्यान लगानें लग गयें थे। उस समय कोई साधन नहीं होनें की वजह से श्री सुमेर सिंह जी नें पहाड से अपनें सिर पर पत्थर ला ला के मैया के मन्दिर का निर्माण चालु रखा। उन्होनें अपने हाथों से श्रधालुओं के बैठनें के लिए चबुतरे बनवाये व पत्थरों के रास्ते बनवाये।

श्री देई माई कुठानियां धाम (गूंगी माई) जिले की सिंघाना पंचायत समिति के कुठानिया गांव में है। मंदिर से सिंघाना कस्बे की दूरी महज 7 किलोमीटर है। सिंघाना में नारनौल बस स्टैंड चौराहा (सर्किल) है जहां से मंदिर के लिए ऑटो व टैक्सी मिलते हैं। सिंघाना कस्बे के मुख्य बाजार से बसें भी जाती हैं।बस स्टैंड से तातीजा जाने वाली बसें मंदिर के पास से होकर गुजरती हैं। इन बसों के आने व जाने का निश्चित समय होता है।सिंघाना के नारनौल बस स्टेंड सर्किल पर दिल्ली, जयपुर, सीकर, चिड़ावा, झुंझुनू, बीकानेर, बठिंडा, अलवर आदि सभी शहरों से सीधी बस सेवा है। यहां से 24 किमी दूर चिड़ावा रेल स्टेशन है। 50 किमी दूर लोहारू (हरियाणा) रेलवे स्टेशन से उतरकर बस के जरिए भी सिंघाना पहुंच सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री ने बांटे 51 हजार युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 51 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। इन अपॉइंटमेंट लेटर पानी वाली युवाओं को अलग-अलग विभागों में नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली के रायसिना रोड स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। रोजगार मेला के तहत देश के अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े युवाओं को 51000 अपॉइंटमेंट लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटे हैं। बता दें कि देशभर के 46 स्थान पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इस रोजगार मेले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भर्तियां हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार की नियुक्तियों में महिलाओं की संख्या भी अधिक है। ये नारी सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है।

दो दिवसीय चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे अखिलेश

लखनऊ। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। जहां एक ओर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 और उम्मीदवारों की घोषणा की तो वहीं प्रियंका गांधी अगले महीने मध्य प्रदेश के धार जिले में रैली को संबोधित करेंगी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब मध्य प्रदेश की यात्रा करने वाले हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अखिलेश यादव 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर रहेंगे। वे रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में आमसभा करेंगे। इस बीच भाजपा की बात करें तो पार्टी ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है।

उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम देख हैरान हुए कैलाश

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें मैदान में उतारने का केंद्रीय नेतृत्व का फैसला उनके लिए किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है और वह अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का आदेश है। मुझसे कहा गया कि मुझे ऐसा काम सौंपा जाएगा जिसके लिए मैं ना नहीं कहूंगा और मुझे वह करना होगा। जब टिकट की घोषणा हुई तो मैं भी हैरान रह गया। मैं पार्टी का सिपाही हूं। वे जो कहेंगे मैं वही करूंगा। विजयवर्गीय ने यह बात सोमवार को भाजपा द्वारा जारी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में अपना नाम आने के कुछ घंटों बाद कही। विजयवर्गीय को इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर-1 निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी ने मैदान में उतारा है।

मध्यप्रदेश में भाजपा की दूसरी सूची पर कांग्रेस का तंज

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को कुल 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा की दूसरी सूची को लेकर तंज कसते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। कांग्रेस ने रामायण का उदाहरण देते हुए लिखा, हार को सामने देख कर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाद सबको उतार दिया था, बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। मध्यप्रदेश में भाजपा की दूसरी लिस्ट पर तंज कसते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। 18 सालों में मध्यप्रदेश को भाजपा की सरकार ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। ये बात प्रदेश की जनता के साथ साथ भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी जान रहा है। इसीलिए 15 दिन पहले अमित शाह और सोमवार को मोदी ने शिवराज के नाम और काम से किनारा कर लिया। ये बात शिवराजसिंह जी को मन ही मन बहुत सालती थी। दूसरी ओर सिंधिया भी अपनी लोकसभा की हार तथा अपने क्षेत्र में लगातार स्थानीय निकायों की हार से भी हताश थे।

कपिल सिब्बल ने अन्नाद्रमुक के राजग से बाहर जाने पर भाजपा पर साधा निशाना

नईदिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके) के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से बाहर निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और कहा कि एक और सहयोगी ने उन्हें छोड़ दिया है और जो अब भी उनके साथ हैं, वे ''अवसरवादी गठबंधन हैं जिनका वैचारिक रूप से कोई जुड़ाव नहीं है।' भाजपा के साथ अपने चार साल पुराने गठबंधन को समाप्त करने का ऐलान करते हुए अन्नाद्रमुक ने सोमवार को घोषणा की थी कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अलग मोर्चे का नेतृत्व करेगी। सिब्बल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'अन्नाद्रमुक राजग से अलग हो गई है। जो दल अब भी उनके साथ हैं, वे बिना किसी वैचारिक जुड़ाव वाले अवसरवादी गठबंधन हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में पवार एवं शिंदे और पूर्वोत्तर में उनके गठबंधन।'

प्रधानमंत्री ने कहा- जी20 की सफलता पर मुझे आश्चर्य नहीं

पिछले 30 दिनों में नई ऊंचाई पर पहुंची भारत की कूटनीति : मोदी

नईदिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में भाग लिया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जी20 के आयोजन को भारत ने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, उसे देखकर दुनिया बहुत चकित है। लेकिन मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं। क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा आप जैसे युवा विद्यार्थी उठा लेते हैं, तो फिर उसका सफल होना तय है। उन्होंने कहा कि आप युवाओं की वजह से पूरा भारत ही एक घटित होने वाला स्थान बन गया है। ये कितना हैपेनिंग है, ये पिछले 30 दिनों को देखकर ही साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी- India is on the Moon। 23 अगस्त की तारीख हमारे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अमर हो गई।

मोदी ने कहा कि इधर चंद्रमा मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सौर मिशन लॉन्च कर दिया। चंद्रयान अगर 3 लाख किमी गया, तो ये 15 लाख किमी तक जाएगा। मोदी ने कहा कि पिछले 30 दिनों में भारत की कूटनीति नई ऊंचाई पर पहुंची है। जी-20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। भारत के प्रयास से ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज के ध्रुवीकृत अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना, छोटा काम नहीं है। आप एक पिकनिक की तैयारी करें तो भी तय नहीं कर पाते कि कहां जाएं। उन्होंने कहा कि जी20 से ठीक पहले इंडोनेशिया में भी मेरी अनेक वैश्विक नेताओं के साथ बैठक हुई। उसके बाद इसी भारत मंडपम में जी20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे नईदिल्ली डिक्लियरेशन को लेकर 100 प्रतिशत सहमति तो आजकल अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जी20 समिट की समाप्ति के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की दिल्ली में स्टेट विजिट शुरू हुई। सऊदी अरब भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 30 दिनों में ही भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मेरी कुल 85 वैश्विक नेताओं से मीटिंग हुई है। ये करीब आधी दुनिया के बराबर है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 दिनों में एससी-एसटी-ओबीसी के लिए, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए, उनको इनपॉवर करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर, पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। ये योजना हमारे शिल्पकारों, कुशल कारीगरों, पारंपरिक काम से जुड़े साथियों के लिए है।

गृह मंत्रालय अर्बन नक्सल की हकीकत बताएं : तृणमूल सांसद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते सोमवार को भोपाल में विपक्षी दल कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए उनके लिए कहे अर्बन नक्सल और टुकड़े-टुकड़े गैंग को लेकर विपक्षी दलों में काफी गहमागहमी है। अब इस मामले में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दखल दिया है और तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी के भाषण में कहे अर्बन नक्सल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और उसने ऐसे संगठनों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। साकेत गोखले ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि कई मौकों पर विपक्षी राजनीतिक दलों, कुछ पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। साकेत ने गृह मंत्रालय में आंतरिक मामलों के विशेष सचिव को लिखे पत्र में अर्बन नक्सली समूह का विवरण मांगा है और पूछा है कि आखिर भारत सरकार ने ऐसे समूहों की पहचान कैसे करती है और कथित अर्बन नक्सलियों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने किस तरह की आधिकारिक एसओपी अपनाई है। इसके साथ ही गोखले ने मोदी के टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले कथन पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि कुछ साल पहले गृह मंत्रालय ने उन्हें रिकॉर्ड पर बताया था कि ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। साकेत गोखले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान बेहद महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने कहा, चूंकि पीएम मोदी ने स्वयं इस बात को कहा है। इसलिए देश को यह जानने की जरूरत है कि भारत सरकार और पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से अर्बन नक्सल की पहचान कैसे की है और पीएम मोदी की कल की गई टिप्पणियों पर भारत सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड क्या है? इसके साथ ही गोखले ने पत्र में यह भी लिखा है कि पीएम मोदी ने बेहद चौंकाने वाला आरोप लगाया और यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि खुद पीएम ने ऐसे समूह के अस्तित्व होने का संकेत दिया है। तृणमूल नेता ने गृह मंत्रालय से यह पूछते हुए कि क्या उसने शहरी नक्सली नाम से किसी अलग श्रेणी की पहचान की है और अगर ऐसी कोई श्रेणी है तो उनसे संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों और उनकी पहचान के आधार गृह मंत्रालय साझा करे।

कांग्रेस नेता का दावा आप के 32 विधायक हमारे संपर्क में

भगवंत मान ने किया पलटवार

नईदिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, पर जुबानी जंग छिड़ गई है। मंगलवार को प्रताप सिंह ने एक्स पर जाकर मुख्यमंत्री की पिछली पोस्ट पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, %आपने अपने चुटकुलों से पंजाब के विकास की भ्रूण हत्या कर दी है।% उन्होंने आगे लिखा कि न आपने कानून व्यवस्था की परवाह की, न अर्थव्यवस्था की, न पंजाब के युवाओं को नशे से बचाने की, न आपने और आपके बॉस की और आप कनाडा में बैठे प्रवासी पंजाबियों की। कोई पक्ष में एक शब्द भी कह सकता है। वहीं, कांग्रेस नेता ने एक और हमला करते हुए कहा कि पंजाब पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। 7-8 महीने में संसद के चुनाव आने वाले हैं। मैं पंजाबियों के सभी वर्गों से अपील करता हूं - अभी भी समय है, कांग्रेस सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन करें और हमें सभी 13 सीटें जिताएं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसके बाद सरकार दो महीने भी नहीं चलेगी। मौजूदा सरकार में कम से कम 32 लोग मेरे संपर्क में हैं। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के साथ बाजवा के दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। बाजवा को भाजपा से जुड़े नेता के रूप में संदर्भित करते हुए, मान ने उन्हें आलाकमान से बात करने की चुनौती दी।प्रताप ने राज्य सरकार से पूछा कि पंजाब के लोगों के रंगीन सपनों के लिए और कितनी भ्रूण हत्या करनी पड़ेगी? सीएम मान ने इससे पहले एक्स में जाकर बाजवा पर हमला करते हुए कहा था, प्रताप बाजवा (भाजपा), आप पंजाब के लोगों की चुनी हुई सरकार को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि कांग्रेस ने आपकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को मार डाला। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि हूं, कुर्सी का त्रिशूल नहीं।

जदय में सबकुछ ठीक नहीं!

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कई चुनौतियां सामने आती दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी के भीतर भी लगातार अस्थिरता भी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के आवास पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच कथित तौर पर एक-दूसरे के साथ जुबानी जंग हुई। दोनों नेता सोमवार को विधानसभा प्रभारियों की बैठक में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री आवास गये थे। बैठक के बाद, ललन सिंह चौधरी के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वह बार-बार जमुई और बरबीघा क्यों जा रहे हैं, जबकि वह अब इन दोनों स्थानों के प्रभारी नहीं हैं। इससे दोनों नेताओं के बीच विवाद हो गया और चौधरी ने कथित तौर पर कहा कि वह मुख्यमंत्री के निर्देश पर जमुई और बरबीघा जा रहे थे। उस दौरान नीतीश कुमार मौजूद थे लेकिन वे मामले में हस्तक्षेप किये बिना बैठक कक्ष से बाहर निकल गये। सूत्रों ने बताया कि बरबीघा विधायक सुदर्शन कुमार ने ललन सिंह से चौधरी के उनके क्षेत्र में बार-बार आने की शिकायत की थी। घटना के बाद किसी ने भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच आज

राजकोट। टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया। 27 सितंबर को दोपहर 1.30 बजे राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मैच खेला जाएगा। विश्व कप से पहले भारतीय टीम अंतिम द्विपक्षीय मुकाबला खेलेगी। तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है और तीसरे वनडे में जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। पहले दो वनडे में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली, हार्दिक पंड्या और कुलदीप यादव जैसे स्टार खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को आसानी से हरा दिया। भारत ने वनडे प्रारूप में कभी आस्ट्रेलिया का सफाया नहीं किया है। दोनों में से कोई भी टीम अपनी धरती पर या दूसरे की मेजबानी में यह श्रेय हासिल नहीं कर सकी है। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम ने कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना भी पिछले दोनों मैच जीते। टीम संयोजन में बदलाव करके यह सुनिश्चित किया गया कि सभी को मौका मिले। विश्व कप से पहले अब टीम लगातार चौथी वनडे जीत की दहलीज पर है। यह सीरीज 3-0 से जीतने पर उसे पांच बार की विश्व चैम्पियन आस्ट्रेलिया पर मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जायेगी।

भारत- रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल , श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, हार्दिक पंड्या, विराट कोहली, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर।

ऑस्ट्रेलिया- पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कारी, जोश इंगलिस, मैथ्यू शॉर्ट, सीन एबोट, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर संघा, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 78 अंक टूटा निफ्टी 19,700 के नीचे

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रूझानों के बीच हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की गिरावट दर्ज की गई। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 78 अंक टूटा। वहीं, निफ्टी में भी 10 अंकों की गिरावट देखी गई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.09 फीसदी फिसला जबकि स्मॉलकैप सूचकांक 0.33 फीसदी चढ़ा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 78.22 अंक यानी 0.12 फीसदी की गिरावट के साथ 65,945.47 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,078.26 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,865.63 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी में भी 9.85 अंक यानी 0.05 फीसदी की मामूली गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,664.70 अंक पर बंद हुआ।

आयकर विभाग ने एंगल टैक्स नियमों को किया नोटिफाई

नईदिल्ली। आयकर विभाग ने स्टार्टअप कंपनियों द्वारा निवासी और अनिवासी निवेशकों को जारी इक्विटी और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों (सीसीपीएस) के मूल्यांकन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम के नियम 11यूए में बदलाव के तहत यह प्रावधान किया है कि अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों का मूल्यांकन भी उचित बाजार मूल्य पर आधारित हो सकता है। संशोधित नियमों में नियमों के मसौदे में प्रस्तावित पांच नए मूल्यांकन के तरीकों को भी कायम रखा गया है। ये हैं-तुलनात्मक कंपनी एकाधिक विधि, संभाव्य भारित अपेक्षित प्रतिफल विधि, विकल्प मूल्य निर्धारण विधि, विश्लेषण विधि, और प्रतिस्थापन लागत की विधि।

ओयो को दूसरी तिमाही में पहली बार हो सकता है मुनाफा: रिपोर्ट

नईदिल्ली। यात्रा प्रौद्योगिकी ब्रांड ओयो का परिचालन करने वाली ओरैवल स्टेज को पहली बार सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही में 16 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि ओयो के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितेश अग्रवाल द्वारा कंपनी के शीर्ष प्रबंधन को मंगलवार को भेजे गए ई-मेल में यह बात कही गई है। अग्रवाल ने कहा है कि यह साल ओयो का दसवां वर्ष है, जो इसे महत्वपूर्ण और विशेष बनाता है। 'मेरे पास इस अवसर पर साझा करने के लिए समाचार है। अबतक के रुझान से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी पहली बार मुनाफा कमाने जा रही है। तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 16 करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है।' भविष्य की वृद्धि संभावनाओं के बारे में अग्रवाल ने कहा, 'हम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे भविष्य के विकास बाजारों में अपार संभावनाएं देखते हैं।

सात अक्टूबर होगी जीएसटी परिषद की बैठक

नईदिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की अगली बैठक सात अक्टूबर को होगी। जीएसटी परिषद ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर लिखा है कि जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में होगी। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की पिछली बैठक दो अगस्त को हुई थी। परिषद में राज्यों के मंत्री भी शामिल थे। पिछली बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर दांव के कुल अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक में व्यापार जगत को त्योहार बाजार को प्रोत्साहन देने वाले संशोधनों की उम्मीद है। हालांकि, परिषद् की तरफ ये साफ नहीं है कि किन मामलों पर विचार किया जा सकता है।

एशियाई खेल में भारत का लक्ष्य है 100 पदक

मनोज चतुर्वेदी

चीन के हांगझोऊ में एशियाई खेलों की शुरुआत हो चुकी है और भारत ने इसमें अब तक का सबसे बड़ा 921 सदस्यीय दल भेजा है। जिसमें 655 खिलाड़ी और 260 कोच और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। भारत ने खेलों की थीम रखी है, इस बार सौ पार। पर जकार्ता में जीते 16 स्वर्ण सहित 70 पदकों को इस बार 100 के पार पहुंचाना आसान नहीं है। भारत के अधिकांश पदक सात-आठ खेलों में आते हैं और इनमें पिछले खेलों की अपेक्षा पदकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने की गुंजाइश कम है। पर इतना जरूर है कि इन खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सफल हो जाएं, तो लक्ष्य के आसपास तो पहुंच ही सकते हैं।

हम पिछले खेलों में पदक तालिका में आठवें स्थान पर रहे थे। भारत यदि इस बार अपने स्वर्ण पदकों की संख्या को 24-25 तक पहुंचा दे तो वह चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया के बाद पांचवें स्थान पर आ सकता है। यह सुधार करना बहुत मुश्किल नहीं है। पिछले खेलों में हमारी कबड्डी और हॉकी टीमों ने निराश किया था। इन दोनों खेलों के पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्णिम प्रदर्शन किया जा सकता है। इस बार पुरुष और महिला क्रिकेट शामिल किये जाने से दो और स्वर्ण पदकों पर कब्जा किया जा सकता है। इसके अलावा बॉक्सिंग, तीरंदाजी और बैडमिंटन के साथ कुश्ती में भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। जहां तक कुश्ती की बात है, तो इसमें जकार्ता में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने स्वर्ण जीते थे, जिसमें से पूनिया इन खेलों में भी भाग ले रहे हैं। वह लगातार दूसरा स्वर्ण जीतने का माद्दा रखते हैं। पर विनेश की अनुपस्थिति में अंतिम पंघाल स्वर्ण की मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आयी हैं। अमन सहरावत भी स्वर्ण पदक के दावेदार हैं। अंतिम पंघाल ने तो अभी हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को बढ़ाया है। इस तरह, भारत पिछले खेलों में जीते दो स्वर्ण वाले प्रदर्शन को सुधार सकता है।

तीरंदाजी में इस बार कंपाउंड वर्ग के तीरंदाज भारतीय किस्मत को बदल सकते हैं। इसके पुरुष, महिला और मिक्सड टीम वर्ग में भारतीय टीमें एशिया में पहले नंबर पर हैं। बैडमिंटन की बात करें, तो भारतीय कोच पुलेला गोपीचंद का कहना है कि एशियाई खेलों का स्तर ओलिंपिक खेलों से भी अधिक है। वे मानते हैं कि ओलिंपिक खेलों में सीमित खिलाड़ी होते हैं और यहां हर देश को दो खिलाड़ी भेजने की छूट होती है। इस कारण यहां पदक तक पहुंचना आसान नहीं है। पीवी सिंधु के इस वर्ष लगातार खराब प्रदर्शन करने पर भी वह उनको ही पदक का सबसे मजबूत दावेदार मानते हैं। भारत आजकल थॉमस कप चैंपियन है, इस कारण टीम स्पर्धा का स्वर्ण जीत सकता है। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय भारतीय चुनौती को पेश करने वाले हैं। पर सही मायनों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के सबसे मजबूत दावेदार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। इस जोड़ी ने पिछले दो सीजनों में अपने झंडे गाड़ कर अपने को स्वर्ण का मजबूत दावेदार बना दिया है।

एथलेटिक्स और निशानेबाजी ऐसे खेल हैं जिनसे भारतीय प्रदर्शन की तकदीर तय होनी है। पिछली बार भी भारत के पदकों के करीब 40 प्रतिशत से अधिक इन दो खेलों से ही आये थे। इन दोनों खेलों में भारत को इस बार भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, तजिंदरपाल सिंह तूर, पुरुष और महिलाओं की चार गुणा चार सौ मीटर की रिले टीमों के अलावा मुरली श्रीशंकर, चित्रावेल ऐसे एथलीट हैं, जिन्हें बहुत चुनौती मिली भी नहीं। इसके अतिरिक्त भी पदक जीतने के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। भारत पिछली बार 21 खेलों में खाली हाथ लौटा था, यदि इनमें कुछ पदक मिले तो लक्ष्य तक पहुंचने की राह बन सकती है। भारत के प्रदर्शन में चार चांद हॉकी में स्वर्ण आने से ही लगता है। महिला क्रिकेट में स्वर्ण जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है।

परिवर्तन की हवा प्रचंड वेग में बदल गई है: साव

भाटापारा/ रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने परिवर्तन यात्रा के भाटापारा पड़ाव के दौरान संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़कों की दुर्दशा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार 5 साल में न तो शहरी क्षेत्रों को मूलभूत सुविधाएं दिला सकी है और न ही ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सकी हैं। उन्होंने कहा कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक यह सरकार नहीं बना पाई। सड़कों के हालात क्या हैं, आपको मालूम है। शहर और गांव की कैसी दुर्दशा है। विकास कैसे अवरुद्ध हुआ है। यह आपको मालूम है। यदि शहरों में और गांव में केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे न आते तो एक एक रुपए का भी विकास गांव और शहरों में नहीं होता। चाहे मनरेगा का काम हो, डीएमएफ के पैसे हों, 15वें वित्त का पैसा हो, यह मद हैं, जिनसे काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नेशनल हाईवे, मनरेगा, इसी तरह के काम हो रहे हैं। नहीं तो एक रुपए का भी काम ग्राम पंचायत में राज्य सरकार की मद से नहीं हुआ है। उन्होंने परिवर्तन यात्रा पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र के मंत्री लगातार आ रहे हैं। किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 4 मंत्री आ रहे हैं। लगातार केंद्रीय मंत्रियों की इस यात्रा में सहभागिता बनी हुई है। कार्यकर्ताओं में भरपूर उत्साह है। उमंग है। जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। उसके पीछे बड़ा कारण है। पिछले पौने 5 सालों में राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ को जिस तरह से ठगा है, जिस प्रकार से लूटा है। इससे जनता परेशान है। एक तरफ एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। ऊपर से छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। धर्मांतरण का गढ़ बना दिया। नशे का गढ़ बना दिया। माफियाओं का गढ़ बना दिया। प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं। सरकार के जो प्राथमिक काम हैं, विकास की दृष्टि से स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना,

सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, यह प्राथमिक काम भी नहीं हुए। एक नई प्राथमिक शाला न बनाई न खोली। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दो परिवर्तन यात्राएं निकाली हैं। पहली परिवर्तन यात्रा मां दंतेश्वरी के पावन धाम से प्रारंभ हुई है। इस यात्रा के प्रभारी भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा हैं। सह प्रभारी पूर्व मंत्री महेश गागड़ा हैं। इस यात्रा का आज 15 वां दिन है। दूसरी यात्रा 15 सितंबर से आरंभ हुई है जो जशपुर से मां खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर निकली है। वह यात्रा आज बिलासपुर जिले में पहुंची है। पिछले 14 दिनों का जो अनुभव है, हम सब की कल्पना से भी अधिक यह परिवर्तन यात्रा सफल रही है। शुरुआत की जो सभा दंतेवाड़ा भी थी, 12 सितंबर को दंतेवाड़ा पूरा शहर भाजपामय हो गया और एक ऐतिहासिक सभा दंतेवाड़ा में हुई। तब से लगातार इस यात्रा को जनता का भरपूर सहयोग आशीर्वाद और अपार संरक्षण मिल रहा है। लगातार स्वागत सभा, सभा और बड़ी सभाएं हो रही हैं। 43 सभाएं इस दौरान हो चुकी हैं। कल भाटापारा की सभा, बलोदा बाजार की सभा, कसडोल की सभा और दो स्वागत सभाएं हुईं और पूरे रास्ते भर लोगों का हुजूम उमड़ा। यात्रा का जिस प्रकार से स्वागत हुआ है, निश्चित रूप से यह बताता है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का प्रचंड वेग चल रहा है। परिवर्तन की हवा प्रचंड वेग में बदल गई है। राज्य की जनता ने मन बना लिया है कि भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकना है। अरुण साव ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर बरसते हुए कहा कि पूरे प्रदेश का विकास ठप है। दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने का काम चल रहा है। घोटाले का सिलसिला चल रहा है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, शिक्षा में घोटाला, गोबर में घोटाला, गोठान में घोटाला और पीएससी का घोटाला तो अद्भुत घोटाला है।न्यायालय की टिप्पणी आपने देखी होगी। छत्तीसगढ़ के नौजवानों पर ऐसे घोटाले का कितना बुरा असर होगा, इसकी कल्पना करें। लगातार ईमानदारी से युवा मेहनत करते हैं। मां-बाप अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आज उनके सपनों को तोड़ने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। युवा आक्रोशित है। कानून व्यवस्था की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना होती है, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, हद तो तब हो गई जब राजधानी में एडिशनल एसपी के ऑफिस की पार्किंग में 6 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। कबीरधाम की घटना को याद करें। बिरनपुर की घटना को याद करें। अभी हफ्ते भर पहले जो भिलाई खुर्सीपार में जो घटना हुई। मलकीत सिंह नाम के युवक की बर्बर तरीके से हत्या हुई है। जिस इलाके में मुख्यमंत्री का निवास हो, गृहमंत्री का निवास हो, 25 साल के युवक को पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर इतनी बेदर्दी से मारा जाता है कि हत्या करने के बाद उसके शरीर पर खड़े होकर नृत्य किया। यह इस बात को बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह खराब है। प्रदेश को बदहाल करके रखा है भूपेश बघेल की सरकार ने। आज देश में छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कल राहुल गांधी आए थे। याद कीजिए 2018 में क्या वादे किए थे। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, शराबबंदी करेंगे, 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो वादे किए थे वह वादों का हिसाब नहीं देते हैं। फिर से झूठे वादे का पिटारा लेकर आते हैं। फिर से जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। ये ठगने वाले लोग हैं। सिर्फ ठगने के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। बड़े-बड़े वादे फिर से कर रहे हैं। पहले का वादा उन्होंने पूरा किया नहीं और फिर से वादे कर रहे हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए यह परिवर्तन आवश्यक है। भाजपा की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ की खुशी और तरक्की के लिए काम करेंगे। अपराध पर नियंत्रण करेंगे। बहू बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास भाजपा की सरकार करेगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया है। हम छत्तीसगढ़ को खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएंगे।

रायपुर पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा आज राजधानी रायपुर पहुंची। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का रायपुर पहुंचते ही भारी आतिशबाजी के साथ लोगों ने फूल बरसा कर स्वागत किया जगह-जगह भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर अपना आशीर्वाद दिया।

■ जनता और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

भाजपा की परिवर्तन यात्रा में लोगों का हुजूम और भारी भीड़ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नींद उड़ा दी है। लोगों ने अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने और छत्तीसगढ़ में फिर से विकास की धारा बहने के लिए छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने के लिए तैयार है।

रायपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने 10 से अधिक बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा बाईक रैली निकालकर भाजपा की परिवर्तन यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान परिवर्तन यात्रा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रावाभाटा स्थित मां बंजारी मंदिर से आशीर्वाद लेकर परिवर्तन यात्रा राजधानी में प्रवेश की।

परिवर्तन यात्रा का स्वागत करने बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए थे। भाजपा कार्यकर्ता ढोल ङ्क नगाड़े, फूल माला लेकर परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता परिवर्तन रथ के साथ साथ बाइक ङ्क कार से चल रहे थे और जोश ङ्क उत्साह के साथ परिवर्तन परिवर्तन के नारे लगाते हुए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने उपस्थित जनसमुदाय से अपील कर रहे है।

छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारी फिक्की अवार्ड से सम्मानित

रायपुर। देश की प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से अच्छे कार्यों तथा बेस्ट प्रेक्टिसेस पर रा'य के पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाता रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 15 सितम्बर, 2023 को नई दिल्ली में फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग एवार्ड- 2022 के लिए रा'य के तीन पुलिस अधिकारियों को इस प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों में कम्युनिटी पुलिसिंग केटेगरी में जिला दंतेवाड़ा में चलाये गये लोन वर्राटू कार्यक्रम के लिए दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव (आईपीएस), जो वर्तमान में जिला कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक हैं, सर्विलेंस एवं मॉनिटरिंग केटेगरी में जिला राजनांदगांव में चलाये गये त्रिनेत्रम अभियान के लिए तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव एवं वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक, रायपुर श्री मयंक गुर्जर (आईपीएस) तथा वूमेन सेफ्टी केटेगरी में रा'यस्तरीय अभिव्यक्ति कार्यक्रम के लिए श्रीमती पूजा अग्रवाल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, पुलिस मुख्यालय को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग एवार्ड-2022 से सम्मानित किया गया है, जो रा'य पुलिस के लिए गौरव का विषय है।

परिवर्तन यात्रा में गरजीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, कहा-

हर जगह से लबरा-बबड़ा की सरकार को बदलने की आ रही आवाज

बिलासपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस पर हमला किया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में भ्रष्टाचार के नाम से मशहूर है. भूपेश बघेल को लबरा और राहुल गांधी को बबड़ा के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि बबड़ा को समझना चाहिए कि देश के खजाने को 70 साल में खाली कर दिया, और यहां छत्तीसगढ़ में बटन दबाकर अपने खजाने को भरने का काम किए.

बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हर जगह जमीन से आवाज आ रही है, लबरा-बबड़ा की सरकार बदलेंगे. पीएससी, गोबर घोटाला किसानों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है. राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बटन तो मोदीजी दबाते हैं, इनकी सरकार तो खेती बंद करने की बात करती थी. मोदी सरकार में किसानी बजट बढ़ा है.

लेखी ने कहा कि राहुल गांधी रोड से और ट्रेन से यात्रा कर पा रहे हैं, तो वह इसलिए क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, वह ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो केंद्र सरकार का ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 करोड़ बेघरों को घर दे दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीब और बेघरों को आवास में राज्यांश नहीं दे रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के 16 सालो बहनों और पात्र हितग्राहियो को लाभ नहीं मिल पा रहा है.

मीनाक्षी लेखी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्य में गोबर घोटाला कर रही है, जिसने पास गाय नहीं है, ऐसे लोगों को गौ पालक बताकर गोबर घोटाला कर रही है. 2 रुपए किलो में गोबर खरीदकर 10 रुपए में खाद बेच रही है, जिसमें खाद कम मिट्टी ज्यादा होती है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक रुपए चावल मिल रहा है, वो केंद्र सरकार के सहयोग से मिल रहा है. केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन हर व्यक्ति को मुफ्त में लगवाई.

पड़ोसी राज्यों से अवैध परिवहन पर लगेगी रोक

रायपुर। रायपुर संभागायुक्त डॉ संजय अलंग की अध्यक्षता में आज आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती जिले के आयुक्तों एवं जिला दण्डाअधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ सुरक्षा समन्वय बैठक हुई। वीडियों कांन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस बैठक में रायपुर संभाग के ज़िलों से लगे उड़ीसा के संबलपुर, बरहमपुर, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, नुआपाडा ज़िलों के आयुक्त और कलेक्टर-एसपी भी शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान कानून एवं व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर्स को पिछले विधानसभा निर्वाचन की भांति इस बार भी आपसी समन्वय स्थापित कर जिलों के सीमा से अवैध हथियार एवं मंदिरा परिवहन पर कार्यवाही हेतु चेक पोस्ट स्थापित करने तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करने कहा गया।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

एनएमडीसी ने अडानी समूह से समझौता किया रद्द

रायपुर। एनएमडीसी द्वारा अडानी समूह के साथ हुए लौह खनन संबंधी समझौते का अनुबंध रद्द कर दिया है। अडानी समूह के साथ किए गये समझौते/ ऐग्रीमेंट के कारण व्यापक जनविरोध हुआ था, जिस कारण क़ानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण डिपोजिट-13 लौह अयस्क खदान जिसका उत्पादन 3 साल पूर्व प्रारंभ हो जाना था।इस खदान के प्रारंभ होने से राज्य सरकार और सीएमडीसी को लगभग 3000 करोड़ का राजस्व प्रति वर्ष मिलेगा।नवीन खनन नीति के लागू होने माइनिंग लीज जारी के 5 वर्ष के भीतर उत्पादन प्रारंभ नहीं होने से खदान निरस्त हो जाएगी जिससे एनसीएल जो कि एनएमडीसी(केंद्र सरकार की उपक्रम) और सीएमडीसी(राज्य सरकार का उपक्रम) की जॉइंट वेंचर कंपनी है,को दीर्घकालीन वित्तीय नुक़सान होता। अड़ानी समूह के साथ एग्रीमेंट व्यावहारिक रूप से लागू करना संभव ना होने तथा एनसीएल के हितों को ध्यान में रखते एनसीएल की बोर्ड ने इस करार को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया। एनएमडीसी के अधिकारियों ने बताया कि अडानी समूह द्वारा लौह अयस्क खनन संबंधी समझौते में नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। इस संबंध में अडानी समूह को 11 जुलाई 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था कि क्यों ना समझौता रद्द कर दिया जाए। अडानी समूह द्वारा इस संबंध में 22 जुलाई 2023 को जवाब प्रस्तुत किया, जो असंतोषजनक और गैर जिम्मेदाराना था।

पत्रकारों को अब आवास ऋण पर मिल सकेगा अनुदान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर अब प्रदेश में पत्रकार अब किफायती दर पर आवास का सपना पूरा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा पर अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा 'श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना' राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। योजना अंतर्गत 30 लाख तक के आवास ऋण के लिए 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 के बाद से क्रय मकान पर प्रभावशील होगी। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ केवल आवासीय ऋण पर दिया जाएगा तथा क्रय किया जाने वाला मकान छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होना चाहिए। ब्याज अनुदान अधिकतम 30 लाख रुपए के आवास ऋण की सीमा तक दिया जाएगा। संचार प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से अधिसूचित वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी बैंकों से लिए गए आवास ऋण पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा।योजना का लाभ न्यूनतम 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवास कर दैनिक समाचार तथा टी.वी. न्यूज चैनल्स में पंजीकृत समाचार एजेंसियों के सम्पादकीय शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधि तथा अधिमान्यता नियमों की अर्हतादायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्टल्स के सम्पादक एवं स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे।संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लें तभी होगी पात्रता- संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लेने पर ही इस योजना की पात्रता होगी।

मोदी की पोल खुलने पर भाजपा तिलमिला रही: ठाकुर

रायपुर। भाजपा के आरोप पर तीखा पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गरीबों के आवास छीनने वाले मोदी सरकार की पोल खोली तब भाजपा के नेता तिलमिला रहे हैं। कल तक जो भाजपा

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से झूठ की राजनीती कर रहे थे। आज सच सामने आने से मुंह छिपा रहे हैं। यह सच है मोदी सरकार ने ही प्रदेश के लाखो गरीबों से उनका आवास छीना हैं। उनके स्वयं के घर के सपने को कुचला है। भाजपा के नेता मोदी की चाटुकारिता में प्रदेश के गरीबों के साथ हुऐ अन्याय अत्याचार पर भी मौन थे और मोदी के गुणगान करने के लिए राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे थे। मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत लाखों बेघर को घर दिया जा रहा है तब भाजपा नेता राजनीति कर रहे हैं असल मायने में भाजपा गरीब विरोधी है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि आखिर मोदी सरकार ने 2021-22 के लिए आवंटित ग्रामीण क्षेत्रों में 7,81,999 घरों के लक्ष्य को तत्काल प्रभाव से वापस लेकर गरीबों के साथ अन्याय क्यों किया?भाजपा के सांसदो ने गरीबो को उनका घर दिलाने केंद्र में प्रयास क्यों नही किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीबो को आवास दिलाने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे तो भाजपा सांसद मौन क्यों थे।

जातिगत जनगणना से भाग रही है मोदी सरकार: वर्मा

रायपुर । जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है की देश की बहुसंख्यक आबादी ओबीसी वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को आखिर इतनी नफरत क्यों है? स्वयं पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का ढोंग

करने वाले मोदी जी जब-जब पिछड़ा वर्ग को कुछ देने की बारी आती है तब-तब हमेशा ही अन्य पिछड़ा वर्ग को निराशा किया है। देश भर के लगभग सभी ओबीसी वर्ग के नेता जातिगत जनगणना कराये जाने के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से लगातार अनुरोध किया कि जनगणना रजिस्टर में जाति का कालम जोड़ा जाए लेकिन अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैसी प्रचारित करने वाले मोदी सरकार, आरएसएस और भाजपाई नहीं चाहते की ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में न्याय मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। भाजपा और केन्द्र की मोदी सरकार नही चाहती कि पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, समाजिक स्थिति का सही आंकलन हो सके। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कि आरक्षण विरोधी सरकार में पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के मुद्दे पर ही सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना स्श्वष्टष्ट शुरु करवाया। मनमोहन सरकार के द्वारा 2013 में आर्थिक जाति जनगणना पूरी हुई।

बैज बताएँ कि केंद्र ने कब आवास योजना मना किया: शर्मा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश कांग्रेस के शो-पीस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आवास योजना

रोकने के लगाए गए आरोप को सफेद झूठ का पुलिंदा करार दिया है। श्री शर्मा ने चुनौती दी कि बैज प्रदेश को बताएँ कि केंद्र सरकार ने कब इस योजना के लिए मना किया? सच तो यह है कि आज के उपमुख्यमंत्री और तत्कालीन पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पत्र लिखकर मुख्यमंत्री बघेल को प्रधानमंत्री आवास योजना रोकने का दोषी ठहराया था जिसके चलते 8 लाख गरीबों को पक्के आवास की योजना से वंचित होना पड़ा था। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री शर्मा ने कहा कि दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज की संगठन में कोई पकड़ है नहीं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहमोकरम पर इस पद तक पहुँच गए हैं तो अपनी हाजिरी लगाने के लिए इस तरह के बेसिर-पैर के बयान देते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने के बाद से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अब ऊँचे ख्वाब देखने लगे हैं और इसीलिए इस तरह के निरर्थक बयान देकर खुद को अव्वल साबित करने की मशक्कत कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस जिस तरह बयानबाजी के लिए बैज का इस्तेमाल कर रही है।

पॉवर कंपनी में कैशलेस स्वास्थ्य योजना के लिए हेल्प डेस्क का शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी में कैशलेस स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यालय डंगनिया में हेल्प डेस्क (सहायता कक्ष) प्रारंभ कर दिया गया है। इसका शुभारंभ प्रबंध निदेशकगण श्रीमती उज्जवला बघेल एवं श्री एसके कटियार ने फीता काटकर किया। प्रबंध निदेशक श्रीमती बघेल ने इस मौके पर कहा कि यह योजना नियमित और पेंशनर कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रारंभ की गई है, निश्चित तौर पर इस प्रयास से हमारे कर्मियों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। यह योजना 1 अक्टूबर से तीनों पॉवर कंपनी- जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रभावी हो जाएगी।

इस मौके पर स्वास्थ्य योजना के लिए तय की गई क्रियान्वयन सहायता एजेंसी विडाल हेल्थ केयर लिमिटेड बैंगलोर के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शंकर बाली ने प्रबंध निदेशकों को कैशलेस हेल्थ कार्ड सौंपा। उन्होंने कहा कि हमारे 25 वर्षों के अनुभवों का लाभ पॉवर कंपनी को देंगे। यह हमारे लिए कार्य करने का बेहतर अवसर है। हम पॉवर कंपनी के सभी अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनर्स को अच्छी सुविधा देंगे। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशकगण सर्वश्री एमएस चौहान, आरके शुक्ला, एके वर्मा, मुख्य अभियंता जी आनंद राव, डीके तुली, अविनाश सोनेकर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता विनोद अग्रवाल, सीएमओ डॉ. एचएल पंचारी एवं डॉ विवेक गोले विशेष रूप से उपस्थित थे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी में नई अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के लिये त्वरित गति से कार्य करते हुए विडॉल हेल्थ केयर प्रा.लि. को काम सौंपा है। कंपनी का हेल्प डेस्क खुलने के बाद अब कर्मियों को हेल्थ कार्ड जारी किये जा रहे हैं। इसके लिए मोबाइल एप भी डेवलप कर लिया गया है, जिसमें कर्मियों को ई-हेल्थ कार्ड, नेटवर्क अस्पताल, भर्ती की सूचना तथा इलेक्ट्रानिक माध्यम से क्लेम जमा करने तथा क्लेम की अद्यतन स्थिति जानने की सुविधा है।

छत्तीसगढ़वासियों को मिलेगा दिल्ली में तोहफा

रायपुर। छत्तीसगढ़वासियों को नया छत्तीसगढ़ निवास तोहफ़े में मिलेगा। नई दिल्ली द्वारका के सेक्टर 13 में बने इस नए छत्तीसगढ़ निवास का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 27 सितम्बर को अपने निवास कार्यालय से इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास भवन की कुल लागत लगभग 60 करोड़ 42 लाख रुपये है। भवन में 61 कमरे, 13 सूट है जो की आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित है।

पिछले तीन सालों में विभिन्न बाधाओं (जिसमें कोरोना काल) को पार कर छत्तीसगढ़ के निवासियों की सेवा के लिये देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक नवनिर्मित छत्तीसगढ़

निवास तैयार किया गया है। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्य एवं चिकित्सा हेतु छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने वाले निवासियों की सुविधा हेतु इसकी परिकल्पना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की थी।

हालांकि, पहले से छत्तीसगढ़ शासन के दो भवन छत्तीसगढ़ भवन चाणक्यपुरी व छत्तीसगढ़ सदन सफ़दरजंग हॉस्पिटल के पास नई दिल्ली में अवस्थित है। परंतु आधुनिक एवं छत्तीसगढ़ की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीसरे भवन की आवश्यकता काफी दिनों से महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने तीन वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास किया था। इसके लिए नई दिल्ली के द्वारका में नये छत्तीसगढ़ निवास के निर्माण की परिकल्पना की गई और इसकी आधारशिला 19 जून 2020 को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल शिलान्यास कर रखी थी। यह पहला मौका है कि जब पहली बार इस प्रकार की महत्वपूर्ण अत्याधुनिक भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से बाहर सफलतापूर्वक सम्पन्न की गई है, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक मील का पत्थर है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.